04 - घट रही है गरीबी या आंकड़ों का मायाजाल

05 - शिक्षा का बाजारवाद या बाजारवाद की शिक्षा

A Daily News Magazine

इंदौर

शनिवार, 19 अक्टूबर, 2024

06 - मरम्मत पर हर साल खर्च हो रहे लाखों रूपये, फिर भी हालात जस की तस

07- बच्चे मिल रही सुविधाओं का लाभ लेकर मन लगाकर...

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 9 अंक 351, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2 (डाक पंजीयन संख्याः MP/IDC/1529/2016-2018)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

क्या हरियाणा से सबक ले राहुल महाराष्ट्र में सामाजिक संतुलन बनाएँगे?

रविकान्त

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद अब सारे देश की निगाहें महाराष्ट्र और झारखंड की चुनाव पर हैं। दरअसल, महाराष्ट्र चुनाव दोनों ही गठबंधनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी का महायुति गठबंधन है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे का महा विकास अघाड़ी गठबंधन है। कुछ दिन पूर्व सम्पन्न हुए हरियाणा चुनाव के नतीजे बेहद अप्रत्याशित रहे। हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी 10 साल की एन्टी इनकंबेंसी का सामना कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने नौजवानों, किसानों और महिला पहलवानों से जुड़े मुद्दों को बड़े पैमाने पर उठाया था। बावजूद इसके हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। हालांकि कांग्रेस ने ईवीएम में धांधली और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

यह भी गौरतलब है कि ज्यादातर विश्लेषक हरियाणा में भाजपा की जीत से स्तब्ध हैं। उनका आरोप है कि 5-6 फीसदी वोटों में हेराफेरी से चुनाव नतीजे प्रभावित हुए हैं। वस्तुतः राजनीतिक विश्लेषक और अन्य बौद्धिक भारतीय लोकतंत्र की गिरती साख से चिंतित हैं। इन आरोपों के बीच हरियाणा चुनाव का एक सामाजिक पहलू भी है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा महीन सोशल इंजीनियरिंग करती है। हरियाणा चुनाव में भी उसने सामाजिक समीकरण बनाये। सीएसडीएस के सर्वे के अनुसार हरियाणा में गैर जाटव दलित, ओबीसी, खत्री और ब्राह्मण वोट भाजपा को मिले। जाट और जाटव बनाम अन्य की राजनीति करके भाजपा ने कांग्रेस को शिकस्त दी। भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को समझे बिना उसे मात देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। आने वाले चुनावों में क्या कांग्रेस हरियाणा चुनाव नतीजों से सबक लेगी?

आगामी महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी के सामने तीन बड़ी चुनौतियां हैं। सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त किये बिना भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी मराठा बनाम अन्य की राजनीति कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार का आधार मराठों के बीच है। इस दरमियान मराठा आरक्षण की मांग का एक बड़ा आंदोलन भी हो चुका है। हरियाणा में जिस तरह गैर-जाटव दलित और ओबीसी वोट निर्णायक रहा, उसी तरह महाराष्ट्र में भी दलित और ओबीसी वोट को विभाजित करके मोदी और शाह महा विकास आघाड़ी को कमजोर कर सकते हैं। हरियाणा में 12 फ़ीसदी दलित और 6 फ़ीसदी बौद्ध हैं। पूरे देश में सर्वाधिक बौद्ध महाराष्ट्र में ही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण डॉ. आंबेडकर द्वारा हिंदू धर्म का त्याग (14 अक्टूबर, 1956) और बौद्ध धम्म को स्वीकार करना है। डॉ. आंबेडकर महार थे। धर्मांतरण के समय अधिकांश महारों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया।

आज महाराष्ट्र में धर्मांतरित बौद्ध आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से बेहद सम्पन्न हैं। अगर दलित और बौद्ध; दोनों को मिला दें तो यह आबादी क़रीब 18 प्रतिशत होती है। लोकसभा चुनाव में दलितों और बौद्धों ने संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को वोट किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर 43 सीटें जीतने वाला एनडीए, 2024 के चुनाव में भाजपा 9, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 7 और एनसीपी अजित पवार एक सीट और एनडीए को कुल मिलाकर 17 सीटों पर जीत हासिल हुई। जबकि महा विकास अघाड़ी को 30 सीटों पर जीत मिली।

संविधान बचाने की मुहिम का असर यह था कि प्रकाश आंबेडकर की बहुजन वंचित अघाड़ी और रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी समेत अन्य दलित राजनीति करने वाली पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन अब संविधान चुनाव जिताऊ मुद्दा नहीं रहा। राहुल गांधी का संविधान बचाने का मुद्दा चुनाव में नैरेटिव तो बना सकता है लेकिन वोट नहीं दिलवा सकता। इसके लिए तीन मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। खासकर दलितों को आकर्षित करने के लिए राहुल गांधी को सम्मान, एजेंडा और प्रतिनिधित्व इन तीनों पर खरा उतरना होगा। हरियाणा में राहुल गांधी ने काम के सम्मान और दलितों के एजेंडे की तो बात की लेकिन कांग्रेस ने सभी जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। गैर-जाटव दलित जातियों, पिछड़ों और अति पिछड़ी जातियों को सम्मानजनक भागीदारी नहीं मिलने के कारण इस वोट को आकर्षित करने में कांग्रेस पार्टी सफल नहीं हुई। महाराष्ट्र में भी दलित, बौद्ध और अन्य ओबीसी जातियों को टिकट वितरण में भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। प्रकाश आंबेडकर और रामदास आठवले जैसे दलित नेता दलित वोट पर अपनी दावेदारी करते हैं। भाजपा हरियाणा की तरह महाराष्ट्र के चुनाव में भी खेल कर सकती है।

प्रकाश आंबेडकर की बहुजन वंचित अघाड़ी लोकसभा चुनाव में किसी सीट पर दूसरे स्थान पर भी नहीं रही, लेकिन उसने इस बार कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ विदर्भ की घोषित 10 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। जाहिर तौर पर प्रकाश आंबेडकर की इस राजनीति से भाजपा को फायदा होगा। प्रकाश आंबेडकर की दावेदारी मूलतः महार और बौद्ध वोटों पर है। विदित है कि विदर्भ में बसपा का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। जाहिर तौर पर मायावती भी अपने प्रत्याशी उतारेंगी। बसपा जाटव समाज को अपने साथ लाने में कामयाब हो सकती है। विदर्भ में कांग्रेस की चुनौती प्रकाश आंबेडकर और मायावती हैं। इससे निपटने के लिए राहुल गांधी को महार और जाटव के साथ-साथ कोरी, खटीक, मांग, मातंग, डोम ओलख और गोतराज जैसी अन्य दलित जातियों को भी प्रतिनिधित्व देना होगा। वस्तुतः ये जातियां अपने नेताओं के कारण भाजपा के साथ जा सकती हैं।

राहुल गांधी के लिए दूसरी चुनौती ओबीसी समाज की है। कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने क़रीब 17 जातियों-उपजातियों को ओबीसी में शामिल किया है। इसके अतिरिक्त क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफारिश की है। राहुल गांधी को यहां जाति जनगणना, आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने का एजेंडा ही नहीं देना होगा, बल्कि माली, धनगर, लोध, बंजारा, लोहार और तेली जैसी पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व भी देना होगा।

महाराष्ट्र की जमीन ज्योतिबा फुले और आंबेडकर की भी मातृभूमि है। इसलिए सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए यह बेहद उर्वर है। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस का हेड क्वार्टर भी है। राहुल गांधी को वैचारिक स्तर पर भी यहाँ मुठभेड़ करनी है। राहुल गांधी के सामने जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन राह रपटीली जरूर है। हरियाणा से सबक लेकर राहुल गांधी महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय के एजेंडे और सामाजिक प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाकर अपनी लड़ाई को आसान बना सकते हैं।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

बाल विवाह कानून में कई खामियां, अवेयरनेस जरूरी

- **एससी बोला-बाल विवाह जीवनसाथी चुनने का अधिकार छीनता है**
- **सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी-इसे पर्सनल लॉ से नहीं रोका जा सकता है**

नई दिल्ली (एजेंसी)। बाल विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा, बाल विवाह रोकने के लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है, सिर्फ सजा के प्रावधान से कुछ नहीं होगा। सीजेआई ने कहा, हमने बाल विवाह की रोकथाम पर बने कानून के उद्देश्य को देखा और समझा। इसके अंदर बिना किसी नुकसान के सजा देने का प्रावधान है, जो अप्रभावी साबित हुआ। हमें जरूरत है अवेयरनेस कैंपेनिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलेंटरी एक्शन ने 2017 में लगाई थी। सोसायटी का आरोप था कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को शब्दशः लागू नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जागरुकता अभियान और प्रशिक्षण जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों पर सवाल उठाते हुए कहा था -ये कार्यक्रम और व्याख्यान वास्तव में जमीनी स्तर पर चीजों को नहीं बदलते हैं।

झारखंड में एनडीए में हो गया सीटों का बंटवारा

पूरा जोर लगाने के बाद भी नीतिश-चिराग को मिलीं 2-1 सीट

रांची (एजेंसी)। चुनावी समर के लिए तैयार हो चुके झारखंड में एनडीए ने सीटों का बंटवारा फाइनल कर लिया है। 81 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा (रामविलास) एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीते कई महीने से झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू और लोजपा (रामविलास) भी तैयारी कर रहे थे लेकिन उन्हें काफी कम सीटें दी गई हैं। झारखंड में दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए विपक्षी दल बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई हुई है। पार्टी ने बेहद अनुभवी और लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री और हिंदुत्व के पोस्टर ब्वॉय हिमंता बिस्वा सरमा जैसे वरिष्ठ नेताओं को झारखंड चुनाव में कमल खिलाने का टास्क दिया है। झारखंड एनडीए में बीजेपी के अलावा आजसू, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी शामिल हैं।

सुप्रभात

अगर मैं गिरा तो प्रेम में गिरा
झुका तो सामने प्रेम खड़ा था
अगर मैं अनैतिक हुआ तो
प्रेम में हुआ
अगर समझौते हुए होंगे तो
प्रेम बचाने के लिए
चालाकियाँ प्रेम पाने के लिए
अगर मैं नालायक था तो
इसलिए कि प्रेम के लायक बन सकूँ
जब लोग असरदारों के सामने गिरे,
झुके, घिघिया रहे थे
और अपनी तरफ़दारियाँ चुन रहे थे
मैं प्रेम में था
मुझे इसके लिए आज भी
लज्जित किया जाता है
शुक्र है मैं बदनाम दुनियादारी के
लिए नहीं हुआ।

- अरुण देव

राज्य सरकार बनाने जा रही है आकर्षक फार्मा पॉलिसी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

● मध्यप्रदेश 160 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है दवाएं ● कॉन्क्लेव के परिणाम ऐतिहासिक, भावी रणनीति के निर्माण की नींव रखेंगे ● वर्ष 2023-24 में प्रदेश से 11 हजार 889 करोड़ रुपये के फार्मा प्रोडक्ट का हुआ एक्सपोर्ट ● पेट्रो-केमिकल इकाइयों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने प्रदेश में की जा रही है पहल ● मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुंबई में इंडिया केम- 2024 के 13वें संस्करण को किया संबोधित

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में केमिकल, फार्मा, पेट्रो-केमिकल और प्लास्टिक जैसे उद्योगों के लिए बेहतरीन इको-सिस्टम विद्यमान है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बीना में भारत पेट्रोलियम की 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पेट्रो-केमिकल परियोजना का भूमि-पूजन किया गया, जिसका कार्य आरंभ हो गया है। प्रदेश में 35 हजार करोड़ की गेल इंडिया की वृहद पेट्रो-केमिकल परियोजना का काम तेजी से जारी है, इससे 25 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। प्रदेश में केमिकल और पेट्रो-केमिकल क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां कार्यरत हैं। प्रदेश में 275 फार्मा यूनिट्स स्थापित हैं, जिनसे 160 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात हो रही हैं। दवा निर्यात में मध्यप्रदेश का देश में चौथा स्थान है। वर्ष 2023-24 में 11 हजार 889 करोड़ रुपये के फार्मा प्रोड्क्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। इस क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने तथा गतिविधियों को विस्तार देने के लिए राज्य सरकार आकर्षक फार्मा पॉलिसी बनाने जा रही है। हम एक फ्यूचर रेडी स्टेट हैं, रसायन और उर्वरक के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयास, आने वाले समय में विकास की नई कहानी लिखने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मुंबई में इंडिया केम-2024 के 13वें संस्करण को संबोधित कर रहे थे।

केमिकल एंड पेट्रो-केमिकल स्ट्रेटजीज पर 'नॉलेज पेपर' का विमोचन- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन व उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ 'इंडिया केम-2024 एडवांटेज भारत : इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रो-केमिकल्स पेविंग द फ्यूचर' के 13वें द्वि-वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

मध्यप्रदेश, औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयासरत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर है। भारत विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था से बढ़कर 5वें पायदान पर आया है। मध्यप्रदेश, औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में वर्तमान में 250 फार्मेसी और 35 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। केमिकल पेट्रो-केमिकल उद्योग के लिए प्रदेश में आवश्यक अधोसंरचना तैयार है। रायसेन जिले के तामोट, ग्वालियर के बिलोवा में प्लास्टिक पार्क तथा रतलाम में वृहद फार्मा बायोटेक केमिकल जोन का विकास हो रहा है।

रीजनल इंड्रस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योग समूहों ने निवेश के लिए की पहल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिकीकरण तथा निवेश के क्षेत्र में केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन आरंभ किया गया है। अब तक उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुकी हैं। अगली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शीघ्र ही रीवा में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के उद्योगों के लिए संभावनाएं विद्यमान हैं। उद्योग समूहों तथा निवेशकों को इससे अवगत कराने और राज्य सरकार की नीतियों के बारे में बताने के उद्देश्य से मुम्बई सहित कोयंबटूर, बैंगलुरू और कोलकाता में रोड-शो किए गए हैं। प्रदेश में निवेश के लिए कई उद्योग समूहों ने पहल की है।

सद्गुरु के फाउंडेशन के खिलाफ बंधक बनाने का केस बंद

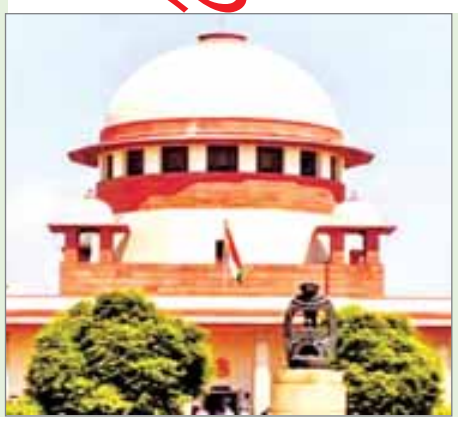

सुप्रीम कोर्ट बोला-लड़कियां बालिग, मर्जी से आश्रम में रह रहीं, वहां पुलिस जांच गलत

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने दो लड़कियों को बंधक बनाने के मामले में सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि मद्रास हाईकोर्ट का ऐसी याचिका पर जांच के आदेश देना सही नहीं था। आश्रम में पुलिस का छापा भी गलत था। कोर्ट ने कहा कि लड़कियों के पिता की याचिका गलत है, क्योंकि दोनों लड़कियां बालिग हैं, जब वे आश्रम में गई तो उनकी उम्र 27 और 24 साल थी। वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले का असर सिर्फ इसी केस तक सीमित रहेगा। ईशा फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उनका आरोप था कि आश्रम में उनकी बेटियों लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया है। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को मामले के खिलाफ जांच करने और ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी क्रिमिनल केसों की डिटेल पेश करने का आदेश दिया था। अगले दिन 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी फाउंडेशन के हेडक्वार्टर पहुंचे थे। सद्गुरु ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को मद्रास हाईकोर्ट के फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगाई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस से पुलिस जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। आज तमिलनाडु पुलिस ने रिपोर्ट पेश की। सुप्रीम कोर्ट में ईशा फाउंडेशन की तरफ से मुकुल रोहतगी ने दलीलें पेश की। वहीं, तमिलनाडु सरकार का पक्ष सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने रखा। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दीं।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 36.3 °c
न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे
इंदौर ■ शनिवार,19 अक्टूबर 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

राज्यपाल कैबिनेट के फैसले मानने के लिए बाध्य

● मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, बोला-वे इसे नहीं बदल सकते

चेन्नई (एजेंसी)। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्यपाल कैबिनेट के फैसले मानने के लिए बाध्य हैं। वे कैबिनेट के फैसले बदल नहीं सकते। मद्रास हाईकोर्ट ने पुझल जेल में 20 साल की कैद की सजा काट रहे कैदी वीरभारती की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। वीरभारती ने राज्य सरकार से अपने अच्छे आचरण की दलील देते हुए जल्दी रिहाई की मांग की थी। स्टालिन कैबिनेट ने वीरभारती की जल्दी रिहाई की मंजूरी दे दी, लेकिन गवर्नर आरएन रवि ने राज्य सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। उन्होंने ही वीरभारती को हाईकोर्ट में याचिका लगाने को कहा था। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएम सुब्रह्मण्यम और जस्टिस शिवाग्नानम की बेंच ने कहा कि गवर्नर आरएन रवि का इस मामले में कोई व्यक्तिगत, नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। बेंच ने वीरभारती को प्रक्रिया खत्म होने तक अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया। वीरभारती ने कहा- बाकी दोषियों की रिहाई नहीं अटकी वीरभारती ने अपनी याचिका में कहा- इस तरह के अपराधों में दोषी ठहराए गए दूसरे कैदियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। राज्य समिति ने पहले अच्छी तरह से जांच की थी। इसके बाद मेरी रिहाई की सिफारिश जरूरी दस्तावेजों के साथ सीएम को भेजी गई थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मामले को राज्यपाल के पास भेजा गया था।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है गवर्नर-स्टालिन के बीच का विवाद

तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। नवंबर 2023 में राज्यपालों के विधेयक अटकाने के मामले में सुनवाई हुई थी। बिल पर साइन न करने की शिकायत को लेकर केरल और तमिलनाडु सरकार ने याचिकाएं दायर की गई थीं। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि हमने देखा कि गवर्नर आरएन रवि ने दस बिलों पर अपनी मंजूरी तब तक नहीं दी जब तक हमने राज्य सरकार की याचिका पर गवर्नर को नोटिस नहीं भेजा। ये बिल तीन साल से पेंडिंग थे, गवर्नर तीन साल तक क्या कर रहे थे। बिलों पर ऐक्शन न लेना गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और राज्य सरकार को आपसी मुद्दा सुलझाने के लिए एक साथ बैठकर चर्चा करने की नसीहत दी थी।

संक्षिप्त समाचार

इस ठंड दम घोंटेगा पाकिस्तान से आने वाला पराली का धुंआ

नई दिल्ली (एजेंसी)। नवंबर-दिसंबर में पराली जलाना हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है, यह बताने की जरूरत नहीं। पंजाब-हरियाणा में बड़े पैमाने पर जलने वाली पराली देश की राजधानी

दिल्ली की हवा दमघोंटू बना देती है। हर साल इन्हीं दो महीनों में पराली का धुंआ, वाहनों के धुंए से मिलकर दिल्ली को प्रदूषित रखते हैं। इस बीच स्पेस एजेंसी नासा ने अपनी सैटेलाइट इमेज से कुछ हैरान करने वाले विजुअल्स हमें दिखाए हैं। इस बार पराली का धुंआ खतरनाक रूप से पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी आ रहा है।

महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारे पर फंसा पेच

मुंबई (एजेंसी)। महाविकास अघाड़ी में टिकट बंटवारे पर मतभेद सामने आने लगे है। सूत्रों के अनुसार, अघाड़ी में 288 सीटों में 260 सीटों पर सहमति बन गई है, बाकी के 28 सीटों पर गठबंधन सहयोगियों में खींचतान हो रही है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से विदर्भ में पांच

सीटें मांगी है। करीब 9 घंटे की मैराथन बैठक में सीटों पर फैसला नहीं होने पर शिवसेना (यूबीटी) ने नाराजगी जाहिर की है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं। सीट बंटवारे पर वह राहुल गांधी से बात करेंगे। हालांकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि गठबंधन में सभी ठीक है। कोई खटपट नहीं है।

हरियाणा का युवक अमेरिका में मोस्ट वॉन्टेड घोषित

जालंधर/रेवाड़ी (एजेंसी)। अमेरिका सरकार ने दावा किया है कि न्यूयॉर्क में रह रहे सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में हरियाणा के रेवाड़ी का युवक भी शामिल है। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन ने युवक विकास यादव का मोस्ट वॉन्टेड पोस्टर जारी

किया है। इस में विकास की 3 फोटो हैं। इनमें एक फोटो में वह सेना की वर्दी में भी है। विकास यादव (39) रेवाड़ी जिले के प्राणपुरा गांव का रहने वाला है। अमेरिकी सरकार का दावा है कि विकास, भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में काम करता है। रॉ ने ही पन्नू की हत्या की साजिश रची। विकास को हत्या के लिए किलर हायर करने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया गया है।

एम्स भोपाल में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

भोपाल। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेशानुसार एम्स भोपाल में शुक्रवार 18 अक्टूबर 2024 को सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो.डॉ. अजय सिंह ने संस्थान में सतर्कता और ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर कहा, सतर्कता जागरूकता अभियान हमारे कार्य के सभी पहलुओं में नैतिक प्रथाओं की आवश्यकता की याद दिलाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। एम्स भोपाल में, हम पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए समर्पित हैं। यह कार्यक्रम हमारे कर्मचारियों को आचरण नियम और खरीद की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में शिक्षित करता है और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

कार्यक्रम के दौरान दो महत्वपूर्ण व्याख्यान आयोजित किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के निदेशक श्री राजेश कुमार गुप्ता ने (आचरण नियम) पर व्याख्यान दियाए जिसमें उन्होंने सभी कर्मचारियों के लिए नैतिक दिशा-निर्देशों और आचरण मानकों के पालन के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा मप्र में जेम प्रशिक्षण के लिए राज्य प्रबंधक श्री

मुज़म्मिल क़ुरैशी ने गवर्नमेंट ई.मार्केटप्लेस के माध्यम से खरीद पर व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने सरकारी खरीद में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफार्म के उपयोग के लाभों की चर्चा की। उप निदेशक (प्रशासन) कर्नल डॉ. अजीत कुमार ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सतर्कता की आवश्यकता और जागरूकता कार्यक्रमों की भूमिका को बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम अनुपालन और सुशासन को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा, 'ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना जागृत करना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सुशासन के सिद्धांतों का हर कार्य में पालन हो। कार्यक्रम का समापन एक इंटरएक्टिव सत्र के साथ हुआए जिसमें प्रतिभागियों ने वक्ताओं के साथ सतर्कता, नैतिक आचरण और खरीद प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। एम्स भोपाल केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप सुशासन और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कार्यक्रम सतर्कता जागरूकता अभियान (16 अगस्त से 15 नवंबर 2024) के अंतर्गत आयोजित किया गयाए जिसमें बड़ी संख्या में फैकल्टी सदस्य, नर्सिंग स्टाफ ,अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थान में नैतिक व्यवहार, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देना था।

अब 40 मिनट में पहुंचेंगे बरेली से बदायूं !

नितिन गडकरी का यूपी वालों को दीवाली पर बड़ा तोहफा

फोरलेन निर्माण के लिए 1527 करोड़ रुपये की दी मंजूरी

बरेली (एजेंसी)। यूपी में एक्सप्रेसवे लगातार बन रहे हैं। कई नए एक्सप्रेसवे का काम जारी है। साथ ही पहले से बने हुए एक्सप्रेसवे को भी जोड़ा जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बरेली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बदायूं से बरेली तक फोरलेन निर्माण के लिए 1527 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू होगा, जिससे बरेली से मथुरा तक यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। गडकरी ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। एनएचएआई के अधिकारियों ने छह महीने के भीतर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया है। दरअसल अब बरेली से मथुरा तक 216 किलोमीटर तक हाईवे को चार

चरण में बनाया जाना है। पहले चरण में मथुरा से हाथरस और दूसरे में हाथरस से कासगंज के बीच काम शुरू हो गया है। तीसरे चरण में कासगंज से बदायूं तक काम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की एनओसी नहीं मिलने की वजह से अटका है। बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में गौसगंज क्रॉसिंग पर जाम की समस्या से निपटने के लिए जल्द ही बाईपास का निर्माण किया जाएगा। एनएच-24 को बुखारा रोड से जोड़ने वाले इस बाईपास की चौड़ाई सात मीटर होगी, जिस पर लगभग 22 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पीडब्ल्यूडी ने इस योजना को लखनऊ मुख्यालय भेजा है और जल्द ही बजट जारी होने की उम्मीद है। बरेली-बदायूं फोरलेन परियोजना के लिए दो साल पहले ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसमें बरेली और बदायूं के 70 गांवों की 118 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की गई थी, लेकिन बजट की मंजूरी में देरी होने के कारण काम रुका हुआ था। अब बजट स्वीकृत होने के बाद काम तेजी से आगे बढ़ेगा। अधिकारी बरेली से बदायूं के बीच जमीन चिह्नित कर रहे हैं। मुआवजा तय हो चुका है।

ब्रिक्स समिट में शामिल होने रूस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी

22-23 अक्टूबर को समिट, यहां चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात संभव

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को होनी वाली ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। रूस इस साल 16 वीं ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहा है। रूस के कजान में होने वाली इस समिट के दौरान, पीएम मोदी सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी समिट में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। दोनों के बीच आखिरी बार 2022 में इंडोनेशिया के बाली में जी 20 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी। इस साल जुलाई में मोदी रूस दौरे पर गए थे। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने उन्हें ब्रिक्स समिट के लिए न्योता दिया था। मोदी जुलाई में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को गए थे।

इजराइल ने हमास के चीफ सिनवार को भी कर दिया ढेर

● यही आतंकी 7 अक्टूबर के हमले का था मास्टरमाइंड ● नेतन्याहू बोले-अब हिसाब बराबर, लेकिन जंग जारी रखेंगे

तेल अवीव (एजेंसी)। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले का मास्टरमाइंड हमास चीफ याह्या सिनवार मारा गया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने गुरुवार रात को सिनवार की मौत की पुष्टि की। नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज में कहा- हमने हिसाब चुकता कर दिया, लेकिन जंग अभी जारी है। दरअसल इजराइल

डिफेंस फोर्सेस ने 16 अक्टूबर को रुटीन ऑपरेशन में दक्षिणी गाजा की एक इमारत पर हमला किया था। इसमें हमास के 3 सदस्यों के मारे जाने की खबर आई। बाद में पता चला कि इनमें से एक याह्या सिनवार है। सोशल मीडिया पर इसके फोटो वायरल हुए। इसमें उसके चेहरे, दांत और घड़ी से दावा किया गया कि मारा गया शख्स याह्या सिनवार है। सिनवार की मौत की जांच के लिए डीएनए टेस्ट किया गया। जंग शुरू होने के एक साल 16 दिन में सिनवार का खात्मा 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 3 हजार से ज्यादा रॉकेट दागे थे। इसके अलावा कई सौ लड़ाके इजराइल में घुसे थे, जिन्होंने कई इजराइलियों को मारा और 200 से ज्यादा को बंधक बना लिया था। इसी दिन से इजराइल ने सिनवार की तलाश शुरू कर दी थी।

राजस्थान की चुनावी जंग में कांग्रेस को डबल झटका !

हनुमान बेनीवाल ने बढ़ाई टेंशन, बीएपी ने दिखाए तेवर

राजस्थान की सात विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार 18 अक्टूबर से शुरू हो गई है जो कि 25 अक्टूबर तक चलेगी। उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ टिकट के दावेदारों की जोर आजमाईश तेज हो गई है। भाजपा सभी सातों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिलहाल स्थिति साथ नहीं है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि वे सभी सातों सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। उधर, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया था। वे पार्टियां अब अलग से ताल ठोकने के मूड में है। अगर आरएलपी और बीएपी अपने स्तर पर चुनाव लड़ती है तो उपचुनाव में कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब होना तय है। गठबंधन वाली पार्टी आरएलपी ने कांग्रेस से दो सीटें मांगी है। उधर बीएपी ने भी तीन सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इन पांच सीटों पर अगर कांग्रेस ने आरएलपी और बीएपी की शर्तें नहीं मानी तो जीत आसान नहीं होगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली पार्टी आंखें दिखा रही हैं।

जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड के प्रस्ताव को उमर कैबिनेट की मंजूरी

● मुख्यमंत्री उमर पीएम मोदी से 2 दिन में मुलाकात कर ड्राफ्ट सौंपेंगे

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक, उमर 2 दिन में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उन्हें प्रस्ताव का ड्राफ्ट सौंपेंगे। उमर ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा। 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद अगले दिन ही उन्होंने प्रस्ताव पास किया। कैबिनेट की मीटिंग में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना मसूद इटू, जावेद अहमद राणा, जाविद अहमद डार और सतीश शर्मा भी मौजूद थे। दरअसल, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए उसे दो यूनियन टेरिटरी (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांट दिया था। पीडीपी ने उमर कैबिनेट के फैसले को लेकर कहा कि यह हमारे लिए बड़ा झटका है। उमर सरकार ने स्टेटहुड बहाली का प्रस्ताव क्यों पारित किया। 370 की बहाली पर भी फैसला करना चाहिए था।

युवतियों के साथ पकड़ाया युवक, मोबाइल में मिली अश्लील चैट-वीडियो

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक फ्लैट में युवक-युवतियों को संदिग्ध हालात में पकड़ा। पुलिस ने मुख्य आरोपी फैजान उर्फ गोल्डी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के मोबाइल में अश्लील चैट और वीडियो मिले हैं। डायरी में 200 से ज्यादा ब्रोकर और कस्टमरों के नंबर मिले हैं। मामला लसूडिया इलाके में गुरुवार रात का है। हिंदूवादी नेताओं ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारा। तलाशी के दौरान उसके पास नकली पिस्टल, लाइटर की तरह दिखने वाली रिवाल्वर और तलवार समेत आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई। डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि फैजान पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जब फ्लैट में दबिश दी तब शराब के नशे में युवक-युवती पार्टी कर रहे थे।

इंदौर में पुलिस का छापा; डायरी में मिले 200 से ज्यादा ब्रोकर-कस्टमर्स के नंबर

युवतियों से जबरन देह व्यापार कराने का आरोप

पुलिस को मौके से एक डायरी मिली है। इसमें 200 से ज्यादा मोबाइल नंबरों के साथ कस्टमरों के नाम लिखे हुए हैं। इससे अंदेशा है कि वह युवतियों को देह व्यापार में धकेल रहा था। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक राजकुमार टैटवाल और मानसिंह राजावत ने फैजान पर बंधक बनाकर लड़कियों से देह व्यापार कराने के गंभीर

आरोप लगाए हैं।

ब्रोकर्स को लड़कियों की फोटो भेजकर चैटिंग – फैजान के मोबाइल में कई ब्रोकरों से की गई चैटिंग भी मिली है। इसमें वह लड़कियों की फोटो भेजकर चैटिंग कर रहा है। पुलिस को कुछ ब्रोकर्स के वीडियो भी मिले हैं। साथ ही कुछ वीडियोज में फैजान लड़कियों को नशे की हालत में जबरन शराब पिलाकर डांस भी करवा रहा है। एक वीडियो में तो उसे एक युवती को गांजे का नशा कराते हुए भी देखा गया है।

देवास का रहने वाला आरोपी फैजान

हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक राजकुमार टैटवाल ने कहा कि फैजान कई युवतियों को बंधक बनाकर देह व्यापार में धकेल रहा था। उसकी गतिविधियां इंदौर में लंबे समय से चल रही थीं। टैटवाल की शिकायत के बाद टीआई तारेश सोनी मामले की जांच कर रहे हैं। जांच में सामने आया है कि फैजान मूल रूप से देवास का रहने वाला है। वहीं इंदौर में करीब 1 साल से रह रहा था।

एडीशनल डीसीपी : ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल पर कर रहे जांच

एडीशनल डीसीपी अमरेन्द्र सिंह ने बताया कि फैजान निवासी महालक्ष्मी नगर के मोबाइल में काफी अश्लील वीडियो और डिटेल मिली है। इसके साथ ही कई कस्टमरों और ब्रोकर के नंबर मिले है। इससे पता चलता है कि आरोपी देह व्यापार में लिप्त है। फैजान के मामले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जांच कर रहे हैं।

इंदौर में दोस्त की पत्नी से रेप

पीड़िता से उसके ही घर में की हरकत, पति को देख भागा आरोपी, केस दर्ज

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के राउ में एक महिला ने पति के दोस्त पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला के पति के आने पर आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस के पास रात में शिकायत पहुंची। इस पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। राउ पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शादीशुदा महिला की शिकायत पर शाबिर पुत्र सफुर खान, निवासी हाटपिपल्या देवास के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके पति निजी स्कूल में ड्राइवर है। आरोपी भी यहीं काम करता है। दोनों में अच्छी दोस्ती है। इसके चलते शाबिर का घर आना-जाना लगा रहता था। गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे पीड़िता घर में फ्रिज साफ कर रही थी। घर का मेन गेट खुला था। 7 साल का बेटा बाहर खेल रहा था। इस दौरान शाबिर घर आया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने वॉशरूम जाने की बात कही। वॉशरूम में जाने के दौरान आरोपी शाबिर ने पीड़िता को दोनों हाथ पकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया और दुष्कर्म किया। इसी बीच पीड़िता का पति घर पहुंचा तो उसे देख शाबिर वहां से भाग गया। पीड़िता ने पति और उसके दोस्त को पूरी घटना बताई और फिर थाने पहुंचे।

इंदौर में फैक्ट्री कर्मचारियों में विवाद के बाद हत्या

खाना बनाने की बात पर कहासुनी के बाद सिर पर टामी से किए वार,आरोपी गिरफ्तार

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के बाणगंगा में देर रात हत्या हो गई। यहां फैक्ट्री परिसर में खाना बनाने की बात पर एक कर्मचारी ने टामी मारकर दूसरे कर्मचारी की हत्या कर दी। पुलिस ने देर रात ही इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घटना रिद्धि-सिद्धि फैक्ट्री की है। फैक्ट्री किसी सार्थक साहू की बताई जा रही है। यहां रात करीब 1.10 बजे में फैक्ट्री परिसर में ही रहने वाले धन प्रसाद लोधी, निवासी सागर की हरीश पुत्र आनंद राम चौधरी,जिला पेंड्रा छत्तीसगढ़ से फैक्ट्री परिसर में ही कहासुनी हुई थी। जिसमें हरीश ने धनप्रसाद के सिर पर टामी से तीन से चार वार कर दिए। उसे गंभीर चोट आने के चलते अरबिंदो अस्पताल ले जाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी और मृतक आठ माह से साथ में काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि रात में शराब पार्टी के दौरान एक बजे के लगभग दोनों में विवाद हुआ। पुलिस को घटना के बारे में चौकीदार जगदीश ने एक घंटे बाद जानकारी दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे सिपाहियों ने आरोपी को फैक्ट्री से हिरासत में ले लिया।

डॉक्टर पति समेत चार लोगों पर दहेज प्रताड़ना का केस

कार और 4 लाख नगद देने के बाद भी किया प्रताड़ित,पुलिस ने की जांच शुरू

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर की एक महिला ने डॉक्टर पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। राखी श्रीवास्तव नाम की इस महिला ने लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने अपने पति प्रशांत श्रीवास्तव, ससुर राधेश्याम, सास कल्पना, और ननद मीनाक्षी के खिलाफ दहेज मांगने और उत्पीड़न करने का मामला उठाया है। राखी का दावा है कि शादी के 10 साल बाद भी उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है। लसूड़िया पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, राखी की शादी जुलाई 2017 में प्रशांत श्रीवास्तव से हुई थी और उनके दो बेटे भी हैं। शादी के समय राखी के पिता ने कार, 4 लाख रुपये नकद, और सोने-चांदी के गहने दिए थे। लेकिन ससुराल पक्ष शादी के बाद से ही दहेज को लेकर असंतुष्ट था। राखी के अनुसार, उसे बेटों के पालन-पोषण का खर्च उठाने और कम दहेज देने का ताना देते हुए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अगस्त 2024 में मायके जाने के बाद, जब राखी ने ससुराल वापस आने की कोशिश की, तो उसे दहेज के बिना घर में आने से इंकार कर दिया गया। पुलिस ने राखी की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है।

पेट्रोल डालकर जलाई गई छेड़छाड़ पीड़िता की मौत

इंदौर में इलाज के दौरान छठवें दिन तोड़ा दम; आरोपी के बेटे ने लगाई थी आग

खंडवा/इंदौर (एजेंसी)। खंडवा में 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन पेट्रोल डालकर जलाई गई छेड़छाड़ पीड़िता ने गुरुवार देर रात दम तोड़ दिया। पीड़िता के वकील वीरेंद्र कुमार वर्मा ने मौत की पुष्टि की है। 18 वर्षीय युवती को 12 अक्टूबर की सुबह 10 बजे जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में एडमिट किया गया था। वहां से रेफर किए जाने के बाद इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजन से शुरुआती जानकारी मिली थी कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। जब पीड़िता के बयान हुए तो उसने बताया कि छेड़छाड़ के आरोपी मांगीलाल के बेटे अर्जुन ने पेट्रोल डालकर आग लगाई है। आरोपी युवक हत्या के प्रयास के मामले में जेल में है।

छेड़छाड़ का आरोपी मांगीलाल गिरफ्तार– पुलिस ने गुरुवार को छेड़छाड़ करने वाले आरोपी मांगीलाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मनोज कुमार राय का कहना है कि मांगीलाल भी आगजनी के षड्यंत्र में शामिल था। इसी केस में उसे गिरफ्तार किया है। दरअसल, मृतक के परिजन ने चेतावनी दी थी कि जब तक मांगीलाल गिरफ्तार नहीं हो जाता, तब तक बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

पिता बोले– मेरी बच्ची को न्याय चाहिए– पीड़िता के पिता ने कहा- मांगीलाल मेरी बच्ची को बहला-फुसला कर खेत में ले गया। उसके साथ बलात्कार किया। मेरे भाई को देखकर वह भाग गया। पुलिस वालों ने ढंग से रिपोर्ट नहीं लिखी। दूसरे दिन पता चला कि छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखी है। पीड़ित के पिता ने कहा.. मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार से मेरी विनती है कि अर्जुन को फांसी या 20 साल की सजा दी जाए। मैं गरीब आदमी हूं, मैंने बकरियां बेच दीं।

इंदौर में कार ने दंपत्ति को 300 मीटर तक घसीटा,महिला की मौत

गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ कर पलट दी कार

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में राजेन्द्र नगर और राउ के बीच सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हुआ है। टक्कर के बाद कार दंपती को करीब 300 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। घटना से गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ कर कार पलट दी। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। वहीं उसमें सवार लोगों की तलाश की जा रही है। राजेन्द्र नगर टीआई नीरज बिरथरे के मुताबिक घटना आईपीएस कॉलेज के पास की है। यहां शुक्रवार सुबह करीब 10.45 बजे तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होकर सड़क किनारे सामान बेच रहे दंपती को टक्कर मार दी।

टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ने कार नहीं रोकी बल्कि स्पीड और बढ़ा दी। दंपती को कार ने करीब 300 मीटर तक घसीटा। हादसे के बाद कार में सवार मौके से भाग गया। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सड़क पर मौजूद आक्रोशित

लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर उसे पलट दिया। इधर, मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को सीधा कर सड़क किनारे किया। बाद में उसे थाने ले जाया गया। कार के अंदर नशा करने वाला गोगो पेपर और शराब की बोतल मिली है। जानकारी के अनुसार राहुल चौहान (35) और उसकी पत्नी सपना चौहान (32) महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यहां पर सड़क किनारे इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहे थे। उनके साथ तीन साल की बेटी भी थी।

तेज आवाज में गाने सुन रहा था आरोपी

बिरथरे के मुताबिक कार ड्राइव करने वाले आर्दश पिता गौरी शंकर को हिरासत में ले लिया है। उसने पूछताछ में बताया कि तेज आवाज में गाने सुन रहा था। पीछे देखने में अचानक कार का स्टीयरिंग मुड़ गया। इस दौरान सड़क किनारे दंपती को टक्कर लग गई। हादसे में महिला की मौत हो गई। वहीं बच्ची मामूली घायल है। आरोपी का मेडिकल कराया गया। वह नशे में नहीं था।

इंदौर में 'दाढ़ी हटाओ, प्यार बचाओ' रैली का वीडियो वायरल

क्लीन शेव बॉयफ्रेंड्स के समर्थन में लड़कियों ने उठाए पोस्टर, लिखा– दाढ़ी रखो या गर्लफ्रेंड

इंदौर (एजेंसी)। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कियों का एक ग्रुप 'दाढ़ी हटाओ, प्यार बचाओ' के नारे के साथ रैली निकाल रहा है। वीडियो इंदौर का बताया जा रहा है। इस रैली में लड़कियों ने क्लीन शेव बॉयफ्रेंड्स के समर्थन में तख्तियां उठाई हुई हैं, जिन पर मजेदार और चौंकाने वाले संदेश लिखे हैं, जैसे नो क्लीन शेव, नो लव' और 'दाढ़ी रखो या गर्लफ्रेंड रखो,पसंद तुम्हारी। कुछ लोग इस वीडियो को मजाकिया और मनोरंजक मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ दिखावा या रील्स के लिए किया गया स्टंट बता रहे हैं। हालांकि, इस रैली का असली मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है। यह संभव है कि यह किसी प्रमोशनल इवेंट का हिस्सा हो या सिर्फ मजाक के तौर पर किया गया हो।

यूजर ने लिखा – घर वाले इनकी कुटाई नहीं करते क्या

वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने शेयर किया। वीडियो को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और कई लोगों ने इसे लाइक भी किया है। वायरल वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ऐसा कुछ लड़के करें तो बवाल हो जाएगा। वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, दाढ़ी से क्या दिक्कत है इन्हें? और एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, इनके घर वाले ये देखकर इनकी कुटाई नहीं करते क्या?

टैंकर माफिया के अड्डे पर रेड, बोरिंग सील

निजी बोरिंग से भरे जा रहे थे टैंकर, रहवासियों ने वीडियो बनाकर की थी शिकायत

इंदौर (एजेंसी)। एयरपोर्ट इलाके में नगर निगम ने एक प्राइवेट बोरिंग को सील किया है। कॉलोनी में रातभर बोरिंग चलने और टैंकरों की आवाजाही से लोग परेशान थे। रहवासियों द्वारा निगम अधिकारियों से इस मामले में शिकायत की गई थी। जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है।

जानिए क्या है मामला– जोन 16 के तहत आने वाले वार्ड 15 के शक्ति नगर में शिव मंदिर के पास रूपेश गोस्वामी नामक व्यक्ति द्वारा निजी बोरिंग से पानी निकालकर टैंकरों में भरकर इसे बेचा जाता है। इस संबंध में शक्ति नगर, बाबू मुराई कालोनी और पटेल नगर के रहवासियों द्वारा गोस्वामी के टैंकर का वीडियो बना कर अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा को भेजा गया था और शिकायत की गई। अपर आयुक्त ने खुद टीम भेजी और वीडियो ग्राफी करवाई तो टैंकर भरा हुआ मिला। नगर निगम ने गोस्वामी को नोटिस भी जारी किए, लेकिन इसके बावजूद पानी की बरबादी बंद नहीं हुई।

कांग्रेस नेताओं ने मंत्री विजयवर्गीय से मुलाकात की

नेहरू नगर की जर्जर बिल्डिंगों को तोड़कर हाईराइज बनाने की मांग, खतरनाक घोषित है बिल्डिंग

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने नेहरू नगर की जर्जर बिल्डिंगों को तोड़कर वहां हाईराइज बिल्डिंग बनाने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की है। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री विजयवर्गीय से मिलकर मांग की है कि इन बिल्डिंगों को तोड़कर योजना के अनुसार हाईराइज इमारतें बनाई जाएं। यह जर्जर बिल्डिंगें किसी भी दिन हादसे का कारण बन सकती हैं। कांग्रेस नेता कमलेश पटेरिया और अन्य कांग्रेसियों ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात कर उन्हें नेहरू नगर की जर्जर बिल्डिंगों के फोटो दिखाए और जानकारी दी। उन्होंने मंत्री को बताया कि यहां जल्द से जल्द हाईराइज इमारत बनाई जानी चाहिए और तब तक यहां रहने वाले लोगों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

कृष्णमुरारी मोघे के कार्यकाल में योजना बनाई गई– गौरतलब है कि जब कृष्णमुरारी मोघे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष थे, तब

इन बिल्डिंगों को तोड़कर हाईराइज इमारत बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन एलआईजी के निवासियों ने इसका विरोध किया था। उस समय कुछ निवासियों ने तल मंजिल पर अवैध अतिक्रमण कर अपने फ्लैट का विस्तार किया था और उन्हें किराए पर दे रखा था, इसलिए वे इसे खाली नहीं करना चाहते थे। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक महेन्द्र हार्डिया ने भी कई बार दौरा कर निवासियों को समझाने की कोशिश की थी।

खतरनाक घोषित इमारतों के कई बार गिर चुके हैं छज्जे

नेहरू नगर की ये बिल्डिंगें कई साल पुरानी होकर जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी हैं। यहां कई बार इमारतों के छज्जे गिर चुके हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। लेकिन न तो नगर निगम यहां कार्रवाई कर पा रहा है और न ही हाउसिंग बोर्ड। कुछ निवासी जबरदस्ती इन इमारतों में रह रहे हैं, जबकि कुछ अन्य मकानों में चले गए हैं। इसी तरह की स्थिति एलआईजी में स्थित बिल्डिंगों की भी है। वहां की एक बिल्डिंग को बोर्ड द्वारा खाली कराकर तोड़ दिया गया है, लेकिन अब तक वहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इन जर्जर बिल्डिंगों का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर हाउसिंग बोर्ड भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पा रहा है।

इंदौर में पर्यावरण प्रेमी नागरिक मंच का प्रदर्शन

शहर की मिलों को सिटी फॉरेस्ट घोषित करने की मांग; संभागायुक्त को सौंपा ज्ञापन

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर की मिलों को सिटी फॉरेस्ट घोषित करने के लिए इंदौर के पर्यावरण प्रेमी नागरिक मंच ने शुक्रवार को रीगल चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शहर के अलग-अलग वर्गों के लोग इसमें शामिल हुए। सभी ने इंदौर की सभी मिलों को सिटी फॉरेस्ट के तौर पर घोषित करनी की बात कही। पर्यावरण प्रेमियों ने प्रदर्शन के बाद संभाग आयुक्त दीपक सिंह को ज्ञापन देते हुए मांग की कि शहर की हरियाली को बचाया जाए, पेड़ों की कटाई को बंद किया जाए और शहर की मिलों की हरियाली को सिटी फॉरेस्ट घोषित किया जाए। इंदौर के रीगल चौराहे पर हुए इस प्रदर्शन में डॉ सुभाष बारोड़, अजय लागू, एसएल गर्ग, अरविंद पोरवाल, संदीप खानवलकर, प्रमोद नामदेव, राहुल निहोरे, अशोक दुबे सहित अन्य लोग शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान पर्यावरण प्रेमी नागरिकों ने जानकारी दी की इन्दौर शहर एक समय अपनी हरियाली एवं बाग-बगीचों के कारण जाना जाता था। नौलखा क्षेत्र में नौ लाख पेड़ थे। शहर के कई क्षेत्र आज भी पेड़ों के नाम से ही जाने जाते हैं, जैसे खजूरी बाजार, इमली बाजार, मोरसली गली, बड़ वाली चौकी, पलासिया, लालबाग, बियाबानी आदि।

मिलों के पेड़ बचाने कर रहे मांग

शहर की आबोहवा को सुधारने में पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शहर के मध्य क्षेत्र में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों में प्राकृतिक रूप से निर्मित शहरी वन (सिटी फॉरेस्ट) के कारण न सिर्फ शहर की आबोहवा ज्यादा खराब होने से बची हुई है, बल्कि सघन पेड़ों के कारण भूमिगत जल का स्तर भी खतरनाक स्तर तक घटने (क्रिटिकल होने) से बचा हुआ है। शहर के लिए ऐसे अनमोल दिल और हरे-फेफड़ों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अतः यहां सिटी फॉरेस्ट घोषित किया जाए और शहरहित में निर्णय लिया जाए। साथ ही सभी बन्द मिल परिसरों को सिटी फॉरेस्ट के रूप में विकसित किया जाए।

शहर में सिर्फ 10 प्रतिशत हरियाली

प्रदर्शन के दौरान बताया गया कि 70 के दशक में शहरी क्षेत्र में 30प्रतिशत हरियाली थी, जो वर्तमान में 9-10प्रतिशत के लगभग है। साल 2023 में शहर का ग्रीन इंडेक्स भी मात्र 9प्रतिशत बताया गया है। पिछले मास्टर प्लान (2008 से 2021) में हरियाली का विकास 22प्रतिशत तक होना बताया गया था, परन्तु वह भी 9 या 10प्रतिशत पर ही रह गया है। वर्तमान में शहर में 10 लाख के लगभग पेड़ बताए गए हैं, जबकि रजिस्टर्ड वाहन 31 लाख से ज्यादा एवं जनसंख्या भी 34 लाख से अधिक है।

पांच सालों पर 1.50 से ज्यादा पेड़ काटे

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक आईआईटी इन्दौर की एक रिपोर्ट के अनुसार शहर में पिछले पांच सालों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 1.50 लाख से ज्यादा पेड़ काटे गये। हरियाली घटने, विशेषकर पेड़ कम होने से शहर का तापमान बढ़ रहा है।

कैसी बनें योजनाएं

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि शहरहित को देखते हुए अब ज्यादा से ज्यादा पुराने पेड़ बचाए जाना ही अंतिम विकल्प है। इसलिए विकास की आगामी योजनाएं इस प्रकार बनाई जाएं कि अधिक से अधिक पेड़ों का संरक्षण हो सके।

बीटेक के अंतिम सीएलसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 23 तक

12वीं की मेरिट पर ज्यादातर कॉलेज में होंगे प्रवेश, 23 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराने का मौका

इंदौर (एजेंसी)। बीटेक-बीई जैसे इंजीनियरिंग कोर्सेस में एडमिशन के लिए अंतिम सीएलसी राउंड के रजिस्ट्रेशन 23 अक्टूबर तक होंगे। काउंसलिंग 22 व 23 अक्टूबर को होगी। 12वीं की मेरिट के आधार पर ही ज्यादातर कॉलेजों में छात्रों को सीट अलॉट होगी। हालांकि ज्यादातर प्रमुख संस्थानों एसजीएसआईटीएस, आईईटी व अन्य में सीटें लगभग भर चुकी हैं। इस बार भी सबसे ज्यादा डिमांड कम्प्यूटर साइंस व आईटी की रही। इंदौर में 23 कॉलेजों के लिए यह काउंसलिंग हो रही। यहां करीब 18 हजार सीटें हैं, जबकि प्रदेशभर में करीब 55 हजार सीटें हैं। ज्यादातर कॉलेजों में 50 प्रतिशत तक ही सीटें भर पाई हैं। इस बार 1200 सीटें एसजीएसआईटीएस में तथा 550 सीटें डीएवीवी के आईईटी में हैं। जानकारी के अनुसार इस बार इंजीनियरिंग कॉलेजों में 60 से 65 फीसदी सीटें भर सकती हैं। हालांकि कुछ ब्रांच में डिमांड बहुत कम रही है। पांच से छह ब्रांच ऐसी रहीं, जिनमें डिमांड बढ़ी है। इनमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच के अलावा कुछ और ब्रांस शामिल हैं।

संपादकीय

असम में लाखों आप्रवासियों को राहत

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नागरिकता कानून की धारा 6 ए को 4-1 के बहुमत से सही ठहरा कर इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इससे असम में 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 के बीच बंगला देश से आए लाखों लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद आए बाहरियों के लिए मुश्किल खड़ी होगी। कभी असम में बाहरी घुसपैठ के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाने वाली आल असम स्टूडेंट यूनियन तथा राज्य के विपक्षी दलों ने इस पैसले का स्वागत किया है। लेकिन परोक्ष रूप से यह राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए झटका है। गौरतलब है कि असम स्टूडेंट यूनियन तथा भारत सरकार के बीच 1985 में हुए समझौते को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में यह प्रावधान संशोधन के जरिए किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा ने बहुमत से फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई। सर्वोच्च अदालत ने धारा 6 एक की संवैधानिकता पर सवाल उठाने वाली 17 याचिकाओं पर चार दिनों तक लगातार सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा कि धारा 6 ए असम के सामने आने वाली एक अनोखी समस्या का राजनीतिक समाधान था क्योंकि शरणार्थियों की आमद ने इसकी संस्कृति और जनसांख्यिकी को खतरे में डाल दिया था। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस अधिनियम को अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह असम के लिए अद्वितीय था। असम में आने वाले प्रवासियों की संख्या और संस्कृति आदि पर उनका प्रभाव असम में अधिक है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, असम में 40 लाख प्रवासी पश्चिम बंगाल के 57 लाख प्रवासियों से अधिक हैं क्योंकि असम में भूमि क्षेत्र पश्चिम बंगाल की तुलना में कम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अर्थ यह है कि असम में 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच बांग्लादेश से आए अनिवासी भारतीय नागरिकता के पात्र हैं। जिन लोगों को इसके तहत नागरिकता मिली है, उनकी नागरिकता बरकरार रहेगी। 1985 में संशोधित नागरिकता अधिनियम के अनुसार बांग्लादेश सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों से असम आए थे, और तब से पूर्वोत्तर राज्य के निवासी हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 के तहत खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। हालांकि कोर्ट ने केन्द्र सरकार की इस दलील को माना कि असम में अनियंत्रित आप्रवासन ने इसकी संस्कृति को प्रभावित किया है और अवैध इमीग्रेशन को रोकना सरकार का कर्तव्य है। अलबत्ता पीठ में शामिल जस्टिस जेबी पारदीवाला ने फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 6ए भले ही इसे लागू करते समय वैध रही थी, लेकिन समय के साथ इसमें अस्थायी रूप से खामियां आ गई हैं। यह धारा राजनीतिक समझौते को विधायी मान्यता देने के लिए अधिनियमित की गई थी। गौरतलब है कि नागरिकता कानून की नागरिकता कानून की धारा 6ए को 1985 में असम समझौते के दौरान जोड़ा गया था। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह अतार्किक रूप से हैरान करने वाला है कि 6 ए के तहत नागरिकता का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति को पकड़े जाने का इंतजार करना पड़ता है और फिर उसे साबित करने के लिए न्यायाधिकरण में जाना पड़ता है। मेरा मानना है कि यह इस तरह के कानून के उद्देश्य के खिलाफ है। इसमें कोई अस्थायी सीमा नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसके तहत विदेशी के रूप में पकड़ा जाना नहीं चाहेगा। धारा 6ए समय बीतने के साथ असंवैधानिक हो गई है। इससे राज्य पर अवैध अप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने का सारा बोझ भी इसमें जुड़ जाता है।

नजरिया

कुमार कृष्णन

लेखक स्तंभकार हैं।

झारखंड में झूलता 'पेसा कानून'

झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आदिवासियों के अधिकार को लेकर 'पेसा कानून' का मामला गरमाने लगा है। कई जगह नारा गूंजने लगा है– 'पहले पेसा कानून फिर वोट,' 'पेसा कानून नहीं तो वोट नहीं।' राज्यपाल संतोष गंगवार भी कह चुके हैं कि राज्य में 'पेसा कानून' लागू करने की जरूरत है। हालांकि 'आदिवासी बुद्धिजीवी मंच' 'पी–पेसा एक्ट' के तहत नियमावली की बात कर रहा है। यहां 'पी–पेसा' में 'पी' का मतलब उन 23 प्रावधानों से है, जो 'अनुसूचित क्षेत्रों' को विशेष अधिकार देता है। यह मामला इसलिए भी गंभीर हो गया है क्योंकि 29 जुलाई 2024 को 'आदिवासी बुद्धिजीवी मंच' की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने दो माह के भीतर 'पेसा नियमावली' अधिसूचित करने का आदेश दिया था। नवंबर की 13 और 20 तारीखों को झारखंड विधानसभा चुनाव होना हैं, इसलिए आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने वाले बुद्धिजीवी संगठनों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हेमन्त सोरेन का 'झारखंड मुक्ति मोर्चा' चुनावों में 'पेसा कानून' को अपना मुद्दा बनाने में सफल हो जाता है तो राज्य में आदिवासी मतदाताओं का दिल जीतना आसान होगा।

हाल में घोषित झारखंड विधानसभा चुनावों की 13 और 20 नवंबर की तारीखों ने अब तक कछुआ चाल से ठुमक रहे 'पेसा कानून' को फिर से हवा दे दी है। करीब तीन दशक पहले संसद में पारित आदिवासियों के लिए मुफीद इस कानून को लागू करने में झारखंड समेत देशभर की राज्य सरकारें कोताही बरत रही हैं। 'आचार संहिता' के चलते मौजूदा चुनाव में भले ही 'पेसा कानून' पर झारखंड में कोई सकारात्मक पहल ना हो पाए, लेकिन इस मुद्दे को उछाल जरूर मिल सकता है। प्रस्तुत है, इसी विषय पर कुमार कृष्णन का यह लेख।-संपादक

'पेसा कानून' ['पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996'] के 28 साल हो चुके हैं और झारखंड राज्य को बने 24 साल, फिर भी झारखंड ने इसे लागू नहीं किया है। मुंडाओं का नारा, 'अबुआ आतु रे, अबुआ राईज' यानी 'हमारे गांव में, हमारा राज' आज भी गांव-गांव में गूंजता है। बिरसा मुंडा ने इस नारे को विस्तार देते हुए, 'अबुआः दिसुम, अबुआः राईज' यानी 'हमारे देश में, हमारा राज' कहा था। मुंडा अपने इलाके को अपना देश मानते थे। 'झारखंड अलग राज्य' आंदोलन का मूल नारा भी 'अबुआः दिसुम, अबुआः राईज' ही था।

झारखंड गठन के दो दशकों बाद तक अधिकांश सत्ताधारियों ने रैली, जनसभा एवं चुनावी सभाओं में 'अबुआः दिसुम, अबुआः राईज' का नारा बुलंद किया, लेकिन ये लोग सिर्फ नारा देते रहे। हकीकत में इन्हें न तो 'अबुआः दिसुम, अबुआः राईज' की सही समझ थी और न ही पूर्वजों के लंबे संघर्ष एवं 'आदिवासियत' का गुमान था। यदि उनमें 'स्वायत्तता' की समझ होती तो सत्ता पर बैठते ही 'पेसा कानून' की नियमावली बनाकर इसे लागू कर देते। झारखंड में विगत ढाई सौ साल का आदिवासी संघर्ष, अलग राज्य का आंदोलन और 'अबुआः दिसुम, अबुआः राईज' नारे का मूल आधार 'स्वायत्तता' ही है।

'स्वायत्तता' आदिवासी जीवन-दर्शन यानी 'आदिवासियत' की बुनियाद है और 'पेसा कानून' आदिवासियों को 'पांचवीं अनुसूची' क्षेत्र में काफी हद तक 'स्वायत्तता' प्रदान करता है। राजनेता और नौकरशाह 'पेसा कानून' को इसलिए लागू नहीं करना चाहते, क्योंकि खनन माफिया इसके खिलाफ है। 'पेसा कानून' लागू होने से खनन माफिया पर ग्रामसभा का कोड़ा चलेगा।

झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आदिवासियों के अधिकार को लेकर 'पेसा कानून' का मामला गरमाने लगा है। कई जगह नारा गूंजने लगा है- 'पहले पेसा कानून फिर वोट,' 'पेसा कानून नहीं तो वोट नहीं।' राज्यपाल संतोष गंगवार भी कह चुके हैं कि राज्य में 'पेसा कानून' लागू करने की जरूरत है। हालांकि 'आदिवासी बुद्धिजीवी मंच' 'पी-पेसा एक्ट' के तहत नियमावली की बात कर रहा है। यहां 'पी-पेसा' में 'पी' का मतलब उन 23 प्रावधानों से है, जो 'अनुसूचित क्षेत्रों' को विशेष अधिकार देता है।

यह मामला इसलिए भी गंभीर हो गया है क्योंकि 29 जुलाई 2024 को 'आदिवासी बुद्धिजीवी मंच' की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने दो माह के भीतर 'पेसा नियमावली' अधिसूचित करने का आदेश दिया था। नवंबर की 13 और 20 तारीखों को झारखंड विधानसभा चुनाव होना हैं, इसलिए आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने वाले बुद्धिजीवी संगठनों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हेमन्त सोरेन का 'झारखंड मुक्ति मोर्चा' चुनावों में 'पेसा कानून' को अपना मुद्दा बनाने में सफल हो जाता है तो राज्य में आदिवासी मतदाताओं का दिल जीतना आसान होगा।

'आदिवासी बुद्धिजीवी मंच' के विक्टर मालतो का कहना है कि झारखंड में जब 'पी-पेसा' के तहत नियमावली बनी ही नहीं है तो फिर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा कैसे गठित हो सकती है? स्पष्ट है कि फर्जी ग्रामसभा बनाकर जमीन अधिग्रहण, बालू घाटों की नीलामी हो रही है, जो संविधान के खिलाफ है। इससे अदिवासियों का हक छीना जा रहा है। यही नहीं फर्जी ग्रामसभा के जरिए 'डीएमएफटी' और 'ट्राइबल सब-प्लान' की राशि का दुरुपयोग हो रहा है।

विक्टर मालतो के अनुसार तीन तरह की ग्रामसभाएं होती हैं। एक, अनुच्छेद 243(ए) के तहत ग्रामसभा होती है जो ग्राम पंचायत के माध्यम से चलती है। दूसरा, 'वनाधिकार अधिनियम-2006' के तहत ग्रामसभा होती है जो जमीन आवंटन के लिए होती है। तीसरी, ग्रामसभा पारंपरिक होती है, जो संसद से पारित 'पेसा कानून' के तहत चलती है। राज्य सरकार इस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है। इसलिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया जिसने हमारे हक में आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को दो माह के भीतर 'पी-पेसा' के तहत नियमावली अधिसूचित करने का आदेश दिया है।

लगातार बढ़ते दबाव के बीच पंचायती राज विभाग ने 26 जुलाई 2023 को 'पेसा नियम' को लेकर गजट प्रकाशित कर आम लोगों से राय मांगी। इस नियमावली को 'झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली- 2022' नाम दिया गया। इसके जरिए अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभाओं को लघु वन उत्पाद, लघु खनिज, भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम, शराब और नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, धन उधार देने पर नियंत्रण, प्रथागत तरीके से विवाद के समाधान के अधिकार को जोड़ा गया, लेकिन इसको आज तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पंचायती-राज विभाग की निदेशक निशा उरांव का कहना है कि नियमानुसार ड्राफ्ट नियमावली पर 'जनजातीय अनुसंधान संस्थान' (टीआरआई) से सुझाव लिए गये थे। इसके अलावा 14 विभागों का भी मंतव्य लिया गया था। अगस्त 2023 में ड्राफ्ट नियमावली प्रकाशित की गई थी। इस आधार पर करीब 400 अतिरिक्त सुझाव आए। इनमें से 267 सुझाव लिए जा चुके हैं। इस मामले में विधि विभाग से भी सहमति मिल गई है। इसी बीच 'ट्राइबल एडवाइज़री कमेटी' में भी बात उठी। कुछ विधायकों की ओर से आपत्तियां भी आईं जिन पर मंथन किया जा चुका है।

'पेसा' के तहत ग्रामसभा को सशक्त बनाने के लिए मॉड्यूल बनाने को लेकर केंद्र सरकार के पंचायती-राज मंत्रालय ने 15 मार्च 2024 को एक आदेश जारी किया था। इसके तहत लघु वन उत्पाद, लघु खनिज, भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम, शराब और नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, धन उधार देने पर नियंत्रण, प्रथागत तरीके से विवाद के समाधान जैसे छह बिंदुओं पर अलग-अलग कमेटी गठित कर ग्रामसभा को मजबूत करने के लिए मॉड्यूल बनाने को कहा गया था। मंत्रालय ने 30 जून 2024 तक ड्राफ्ट मॉड्यूल और 15 जुलाई 2024 तक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने को कहा था। इस मामले में मॉड्यूल तैयार हो चुका है और चुने हुए मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यही ट्रेनर ग्राम प्रधान को तमाम विषयों पर जागरूक करेंगे।

दरअसल,1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत त्रि-स्तरीय पंचायती-राज को कानूनी रूप मिला था, लेकिन इसमें आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए 1992 में 'पेसा कानून' को संसद ने पारित किया। यह कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को विशेष शक्ति देता है। 'पांचवीं अनुसूची' में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात समेत कुल 10 राज्य शामिल हैं। झारखंड में 24 में से 13 जिले अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, लेकिन अभी तक इन क्षेत्रों में 'पी-पेसा' के तहत नियमावलि नहीं बनी है। नियमावली नहीं बनने पर केंद्र से मिलने वाला फंड बंद हो सकता है। (सप्रेस)

विमर्श

अवधेश कुमार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

भागवत ने आखिर क्यों दिया यह संदेश?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन परिवार इस समय विश्व स्तर पर सबसे बड़े जन समूह और संगठनों वाला विचार परिवार है। संघ के सरसंघचालक का हर वक्तव्य उनके लिए मार्गदर्शन के समान होता है। विजयदशमी संघ की स्थापना का दिवस है। इस कारण भी नागपुर से दिए गए भाषण का सर्वाधिक महत्व हो गया है। पूरा संगठन परिवार ही नहीं हिंदुत्व और संस्कृति आधारित राष्ट्रवाद की विचारधारा को मानने वाले अलग-अलग समूहों एवं उनके विरोधी भी ध्यान से उस भाषण को सुनते हैं। ऐसा पहली बार देखा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने एक्स हैंडल से डॉक्टर मोहन भागवत के भाषण के लिंक को रिपोस्ट किया और आग्रह किया कि इसे अवश्य सुना जाए। इस नाते भी इसका महत्व बढ़ जाता है। डॉ भागवत विजयादशमी के हर भाषण के आरंभ में भारत एक राष्ट्र के रूप में किस तरह सर्वांगीण उन्नति कर रहा है और विश्व में इसकी महिमा, प्रतिष्ठा और साख कैसे बढ़ी है इसकी आवश्यक चर्चा करते हैं। स्वाभाविक ही इससे स्वयंसेवकों एवं कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों के अंदर भारत को लेकर सकारात्मक आत्मविश्वास की भावना सशक्त होती है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय पर मैं बोलने नहीं जा रहा हूं क्योंकि इस समय भारत और विश्व के लिए चुनौतियां एवं खतरे ऐसे खड़े हुए हैं जिनको समझाना और उनका सामना करते हुए समाप्त करना और अपरिहार्य हो गया है। इसमें उन्होंने हिंदू समाज को ही स्वाभाविक रूप से केंद्र में रखा। इसका कारण वह लगातार बताते रहे हैं कि हिंदुओं का संस्कार, चरित्र, जीवन मूल्य और जीवन दर्शन ही ऐसा है जिसमें संपूर्ण विश्व के समुत्कर्ष, कल्याण, शांति - सद्भाव के लिए जीने और काम करने का आधार होता है। इसलिए हिंदू संगठित रहें, खतरों के प्रति सतर्क और इसे समाप्त करने के लिए सक्रिय हों जिससे भारत एक राष्ट्र के रूप में अपने सही लक्ष्य को पहचानते हुए सशक्त रह पाएगा तभी यह संभव होगा।

अगले दिन समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी -' डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को समझना होगा दुर्बल व संगठित होना अत्याचार को निमंत्रण देना है।' अगर देखें तो निस्संदेह यह उनके भाषण का प्रमुख सूत्र था किंतु ऐसा उन्होंने क्यों कहा यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने भाषण के अंत में उन्होंने नवरात्र की चर्चा करते हुए बताया उस पंक्ति को देखिए। 'इसी साधना से विश्व के सभी राष्ट्र अपना- अपना उत्कर्ष याद कर नए सुख, शांति व सद्भावनायुक्त विश्व को बनाने में अपना योगदान करेंगे। उस साधना में आप सभी आमंत्रित हैं।, उनकी उन्होंने एक गीत की पंक्ति दोहराई - हिंदू भूमि का कण-कण हो अब शक्ति का अवतार उठे, जल -थल से अंबर से फिर हिंदू की जय - जयकार उठे , जग जननी की जयकार उठे। तो यह साधना कौन सी है? नवरात्रि में देवी वास्तव में देवताओं के शक्तियों की पुंज थीं लेकिन शक्तिशाधना शील के साथ। इसीलिए उन्होंने कहा कि संघ की प्रार्थना में कोई परास्त न कर सके ऐसी शक्ति और विश्व विनम्र हो ऐसा शील भगवान से मांगा है। विश्व के, मानवता के कल्याण का कोई काम अनुकूल परिस्थिति में भी इन दो गुणों के बिना संपन्न नहीं होता। विश्व की मंगल साधना में मौन पुजारी के नाते संघ लगा है तो उसके पीछे यही सोच है। इसलिए दुर्बल और संगठित होने का अर्थ दूसरे को डराना या हमलावर होना नहीं बल्कि कल्याण के लिए शील संपन्न शक्ति साधना है। उनकी इस बात से हर भारतीय को सहमत होना चाहिए कि भारत विश्व में प्रमुखता पा रहा है तोऐसी शक्तियां और देश हैं जिन्हें अपने निहित स्वार्थ पर खतरा नजर आता है और वह अनेक तरीकों से भारत को कमजोर और अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। इसके दुनिया में उदाहरण है कि चाहे देश पर आक्रमण करना हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को अवैध अथवा हिंसक तरीकों से उलट देना हो, अंदर विद्रोह करना हो ऐसे प्रयास चलते रहे हैं और भारत के विरुद्ध चल रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंसक तख्तापलट की चर्चा करते हुए कहा कि हिंदू समाज पर जिस तरह अकारण नृशंस अत्याचार हुए उसके विरुद्ध हिंदू समाज संगठित होकर स्वयं बचाव में घर के बाहर आया इसलिए बचाव हुआ किंतु वह समाप्त नहीं हुआ है। इससे भारत की कई प्रकार के खतरे बढ़े हैं, इसलिए विश्व भर के हिंदुओं और भारत सरकार के सहयोग की अल्पसंख्यक हिंदुओं को आवश्यकता है। यहीं पर उन्होंने कहा कि असंगठित रहना व दुर्बल रहना यह दूसरों के द्वारा अत्याचारों को निमंत्रण देना है। चूंकि कि बांग्लादेश को पाकिस्तान में भी मिलने की बात हो रही है इसलिए यह सबसे बड़े चिंता का विषय है।

दूसरे खतरे के रूप में उन्होंने डीप स्टेट , वोकिजम, कल्चरल मार्क्सिस्ट की चर्चा करते हुए कहा कि यह सभी सांस्कृतिक परंपराओं के घोषित शत्रु हैं और सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं तथा जहां-जहां जो भी भद्र मंगल है उसका पूरी तरह नाश इनकी कार्य प्रणाली का अंग है। सच है कि देश में कृत्रिम तरीके से मांग, आवश्यकता अथवा समस्या के आधार पर अलगाव के लिए प्रेरित करते हैं, असंतोष को हवा देते हैं और शेष समाज से अलग व्यवस्था के विरुद्ध उग्र बनाते हैं । समाज में टकराव की संभावनाओं को ढूंढ कर टकराव खड़े करते हैं और इस तरह चारों ओर अराजकता और भय का वातावरण पैदा किया जाता है। बताने की आवश्यकता नहीं कि भारत में यह स्थिति हमारे चारों ओर है। दुर्भाग्य से सत्ता के लिए स्पर्धा में अनेक दलों ने यही पद्धति अपनायी और इसकी क्षति देश को हो रही है।

इसमें संस्कार युक्त परिवार और समाज परंपरा में दोष उत्पन्न हो गए हैं और हर स्त्री को माता के रूप में देखने का आचरण कमजोर हुआ है। इसके कारण बलात्कार और अन्य शर्मनाक घटनाएं हो रही है। इसी में उन्होंने कोलकाता के आरजी कार अस्पताल की भी चर्चा की। इसको समाप्त करने के लिए परिवार, समाज तथा संवाद माध्यमों के द्वारा अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रबोधन की व्यवस्था को जागृत करने पर उन्होंने बोल दिया। सीमा क्षेत्र से लेकर चारों ओर संकट खड़ा करने तथा बिना कारण कट्टरपन को उकसाने की घटनाएं हमारे सामने हैं जब हिंदू धर्म यात्राओं पर अकारण पथराव और हमले हो रहे हैं तथा बिना कारण हिंसा व भय पैदा करने की घटनाएं जिसे डॉक्टर भागवत ने गुंडागर्दी कहा और यही सच है। चूंकि यह योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है इसलिए इसे तुरंत नियंत्रित करना, उपद्रवियों को दंडित करना प्रशासन का काम है लेकिन उन्हें हम तक पहुंचे से रोक कर अपने प्राण व संपत्ति की रक्षा का दायित्व तो समाज का ही है। लेकिन जब तक हिंदू समाज जातियों में बंटा रहेगा तब तक यह संभव नहीं होगा इसलिए। मोहन भागवत की यह बात बिल्कुल उचित है कि समाज के सभी वर्गों में कुटुंबों की मित्रता होनी चाहिए, यह व्यक्तिगत तथा पारिवारिक स्तर पर हो तथा श्रद्धा के स्थल यानी मंदिर, पानी, श्मशान, समाज के सभी वर्गों को सहभागी होना ही चाहिए। जातियों के नेतृत्व करने वाले प्रमुख लोग आपस में मिल-बैठकर विचार करें तो सद्भावपूर्ण वातावरण बनेगा और समाज संगठित होगा तथा कोई कुचक्र सफल नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि किस तरह जाति के आधार पर अलग-अलग विषय उठाकर समाज को खंडित करने की कोशिश हो रही है।

इस तरह डॉ. भागवत ने भारत में व्याप्त सभी खतरों, उनके कर्म और यहां तक कि उनके निदान की भी बात की और अगर आपके अंदर कोई वैचारिक घृणा और दुराग्रह नहीं है तो इसे स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे पर्यावरण पर संकट हो, ऋतु चक्र का परिवर्तन, स्वास्थ्य समस्या या समाज के अलग-अलग खतरे उन सबके लिए कुछ सूत्र निश्चित हैं। अपने संस्कारों का जागरण, एक समाज के नागरिक के नाते अनुशासनपरक सामाजिक व्यवहार, भारत एवं हिंदुत्व को लेकर स्व गौरव का भाव, भारत गौरव की प्रेरणा से अपना आचरण, विविधताओं को भेद न मानकर विशेषता मानना, उपभोग में संयम सहिष्णुता तथा दुर्भावना से परे रहना आदि की चर्चा उन्होंने की और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह सब किसी भी राष्ट्र के लिए परम सत्य हैं जो हमारे सह अस्तित्व तथा सहजीवन के रास्ते हैं। लेकिन दुर्बल की सत्यता, सहिष्णुता व मूल्यों की बात कोई नहीं सुनता। इसलिए अगर दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में सद्भावना व संतुलन लाकर शांति और बंधुता की ओर बढ़ना है तो भारत को विशेषकर हिंदुओं को अपने को शक्तिशाली बनाए रखना होगा। बलहीन को कोई नहीं पूछता। इसीलिए उन्होंने संगठित होने की बात की तथा असंगठित होने को अत्याचार बताया।

घट रही है गरीबी या आंकड़ों का मायाजाल

मुद्दा

बाल मुकुन्द ओझा

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र ने अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को मनाने की पहल 22 दिसम्बर 1992 को की थी। यह लोगों के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को उजागर करने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने का एक वैश्विक मंच है। यह दिन गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के महत्व को उजागर करता है। इस वर्ष की थीम सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य करना रखी गई है।

दुनिया भर में गरीबी की स्थिति आज भी बेहद चिंताजनक है। विश्व बैंक के मुताबिक लगभग 700 मिलियन लोग आज भी अत्यधिक गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं। रिपोर्ट से साफ़ होता है, दुनिया की एक बड़ी आबादी आज भी बुनियादी आवश्यकताओं, जैसे भोजन, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच नहीं पाई है। हमारे देश की बात करें तो आजादी के 77 सालों के बाद भारत में गरीब और गरीबी पर लगातार अध्ययन और खुलासा हो रहा है। भारत की गरीबी आज भी आंकड़ों के भ्रम जाल में उलझी हुई है। नीति आयोग की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पिछले नौ वर्षों में भारत में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी के अभिशाप से मुक्त हुए हैं। थिंक टैंक एनसीएईआर के अर्थशास्त्रियों के एक पेपर में गरीबी के आंकड़ों को लेकर किये गए सर्वे में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात में तेजी से गिरावट आई है और यह 2011-12 में 24 प्रतिशत से घटकर अब 8.6 प्रतिशत हो गई है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में गरीबी 13.4 फीसदी से घटकर 8.4 फीसदी हो गई। वहीं मोदी सरकार संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट पर खुश हो सकती है। इस रिपोर्ट में भारत में गरीबी के विरुद्ध लड़ाई में भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की गई है। रिपोर्ट की माने तो गरीबी कम करने के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने पिछले 15 सालों में गरीबों की संख्या में गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2005-06 से साल 2019-2021 के दौरान सिर्फ 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। गरीबी मापने के लिए जीवनस्तर में चूल्हे से लेकर साफ-सफाई, पेयजल, बिजली, घर, संपत्ति और बैंक अकाउंट इत्यादि भी देखे जाते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा का गरीबी के मानकों में शामिल करना गरीबी को सम्यक बनाता है। कुछ सर्वेक्षणों में मोदीराज में भारत में गरीबी घटने की बात कही गयी थी तो कुछ सर्वेक्षणों में गरीबी बढ़ती बताई जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाये तो देश की गरीबी आंकड़ों के मायाजाल में फंसी दिखाई दे रही है। विभिन्न स्तरों पर गरीबी खत्म किये जाने के दावे स्वतंत्र विश्लेषक सही नहीं मानते है। मगर यह अवश्य कहा जा सकता है कि पिछले एक दशक में गरीबी उन्मूलन के प्रयास जरूर सिरे चढ़े है। भारत सरकार ने हर प्रकार की गरीबी को कम करने के लक्ष्य के साथ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसी उल्लेखनीय पहलों ने स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे वंचित रहने में काफी कमी आई है। दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक का संचालन करते हुए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 81.35 करोड़ लाभार्थियों को कवर करती है, जो ग्रामीण और शहरी आबादी को खाद्यान्न प्रदान करती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाना, सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। मातृ स्वास्थ्य का समाधान करने वाले विभिन्न कार्यक्रम, उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन वितरण, सौभाग्य के माध्यम से बिजली कवरेज में सुधार, और स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे परिवर्तनकारी अभियानों ने सामूहिक रूप से लोगों की रहने की स्थिति और समग्र कल्याण की स्थिति में सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जन धन योजना और पीएम आवास योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने वित्तीय समावेशन और वंचितों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में आने वाली मूलभूत समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है ताकि देश एक विकसित राष्ट्र यानी विकसित भारत @2047 बनने की ओर अग्रसर हो सके। सरकारी स्तर पर यदि ईमानदारी से प्रयास किये जाये और जनधन का दुरूपयोग नहीं हो तो भारत शीघ्र गरीबी के अभिशाप से मुक्त हो सकता है।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) - गिरीश उपाध्याय
वरिष्ठ संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

नाश्ते का दर्शनशास्त्र

व्यंग्य

विजी श्रीवास्तव

लेखक व्यंग्यकार हैं।

शहर बड़े हो रहे हैं, परिवार छोटे, दिल और छोटे... रिश्ते तो सिकुड़ कर कुकुरमुत्ते की मानिंद। किसी अपने के घर जाकर पराएपन का भरपूर एहसास कराने वाला, एक आसान पैरामीटर है नाश्ता। इसमें वो पदार्थ पाए जाते हैं जो दर्शनार्थ तो होते हैं, खाने के लिए नहीं होते। नाश्ते का यह सामाजिक विज्ञान शहरों में ही नहीं कस्बों और गॉवों में भी अपनाया जा रहा है।

मेजबान, दरवाजे पर ही मेहमान की फेस रीडिंग कर पहले तो यह याद करता है कि अगले से रिश्ता क्या है। तब अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि उसके आगमन का हिडेन एजेंडा क्या है? फिर भी अपने मत को पुष्ट करने के लिए संवाद के द्वार खोलते हुए वो पूछ ही लेता है - आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए सरकार?

उनकी धारणा है कि चुनावों के बाद सरकार रास्ता नहीं भूलती। वे आशंकित हैं कि बिना बुलाए आई हुई मुसीबत पास के कॉलेज में पुत्र या पुत्री को प्रतियोगी परीक्षा देने के छोड़कर तो नहीं आई हैं, वरना हो गई 3 घंटे की छुट्टी। पर यह जवाब पाकर कि नहीं, इधर ही एक परिचित से कुछ काम था तो सोचा आपके हाल - चाल भी ले लिए जाएं'' ज्बीपी कंट्रोल में रहता है।

द्वितीय प्रश्न 'मेहमान-ए- मुसीबत' की ओर से उछाला जाता है - और सुनाएं, तबीयत पानी क्या बोलती है। सब ठीक है ना? फिर आपस में दो चार परिचितों की थोड़ी बहुत पड़ताल और फिर गहरी चुप्पी। रिश्तों की खराब तबीयत पर कोई बात नहीं होती। इस संवादहीनता को तोड़ेंगी भाभी जी - चाय बना के लाती हूं।

अरे रहने दीजिए। चाय वाय सब लेके ही आ रहे हैं। लेकिन चाय विहीन सत्कार से भारतीय संस्कृति का अपमान न हो जाए इसलिए अतिथि आगमन के 8 से 10 मिनिट की नियत अवधि में तीन क्वार्टर प्लेट, एक चम्मच के साथ और दूसरे राउंड में चाय ट्रे में बैठकर चली आती है। अतिथि ट्रे के हल्केपने से समझ जाता है कि एक प्लेट में किसी पूर्ववर्ती मेहमान से कैरी फॉरवर्ड किए हलकट से ग्लूकोज के बिस्कुट, एक में नमकीन और एक में कोई अन्य रिकरिंग डिपॉजिट होगा। तीनों ही प्लेट्स में बार बार दोहराया जाने वाला इतिहास, नाश्ते की शक्ल में।

भाभी जी बोलेंगी - ''लीजिए न भैया। अरे कुछ तो लीजिए।'' उनके हबी बोलेंगे - ''अरे ले ले यार अभी। फिर कुछ गरम बनवाते हैं।'' बड़ी लड़की बोलेगी- ''अंकल लीजिए न। आपने तो कुछ भी नहीं लिया।'' छोटी लड़की बोलेगी - ''ठीक है अंकल, हम भी आपके घर आएंगे तो कुछ भी नहीं खाएंगे।''

टेबल का राउंड लगाकर मिसेज कौलम्बस ने नाश्ता भूमध्य रेखा पर धर दिया है। अगर गलती से कोई आकर्षक चीज प्लेट में उपस्थित हो तो टेबल एक दर्शनीय स्थल का रूप ले लेती है जिसे कनखियों से देखा जाता है। हमारी संस्कृति में 'अतिथि देवो भव' इसीलिए कहा जाता है कि जैसे देवों के समक्ष प्रसाद रखकर यह मान लेते हैं कि उन्होंने ग्रहण कर लिया होगा, अतिथियों के सामने भी इसी भरोसे के साथ नाश्ता रखा जाता है कि वो ऑखों से खाकर तृप्त हो जाएंगे। उधर अतिथि के मन में विकार उत्पन्न हो रहा होता है कि भोपाल जैसे शहर में 90 लाख का मकान, 3 लाख का ऐसा सोफासेट कि बैठने वाला अपने पृष्ठ भाग पर हाथ फेरकर बैठे, 50 हजार की टेबल.... पर नाश्ता दो कोड़ी का? ऊपर से नाश्ते की दूरी तो देखो। दसों दिशाओं से साढ़े तीन फिट की दूरी, डेढ़ फुट ऊंचा सोफा, बैठने के बाद आपकी चार फुट वर्टिकल ऊंचाई। गणित का कोई भी छात्र लंब बटा आधार के फॉर्मूले से कर्ण यानि आपके हाथ से प्लेट की भौतिक दूरी अंदाज कर यह बता सकता है कि इतनी दूर से चम्मच में नमकीन भरकर मुंह तक लाने पर टेबल, फर्श या सोफे पर गिरने की आशंकाएं कितने प्रतिशत हैं।

लेकिन टेबल और सोफे की दरमियानी दूरी की तुलना में रिश्तों के बीच की दूरी का आकलन दूरबीन से देखकर भी नहीं किया जा सकता। अपनापन और शिष्टाचार के बीच रैडक्लिफ, हिंडेनबर्ग, डूरंड और मैकमोहन लाइन खिंची हुई हैं जिनकी चौकसी, मुस्तैद खड़े बिस्कुट और नमकीन की बारूदी सुरंगे कर रही हैं। भाई और भौजी से रिश्ते भी इमोजी तक सीमित हो गए हैं। वाट्सेप पर बात करते हुए दोनों ओर से हर तीसरी बात की दर से हार्ट की एक रक्ताभ इमोजी तो भेज दी जाती है लेकिन उस दिल में परस्पर जो कालापन है, वो इमोजी से नहीं इमेजिन करने पर समझ आता है।

कभी कभी किसी उदार पति द्वारा पत्नी के इस बिस्कुटाचार पर आपत्ति लगाई जाने पर जवाब मिलता है कि ''आप तो मत ही बोलो। टिट फॉर टेट के इस ज़माने में बात का जवाब बात से और चाय बिस्कुट का जवाब चाय बिस्कुट से देना ही सही रहता है। पति के सारे तर्क बेमतलब हो जाते हैं- ''यार इतनी दूर से बहन आई थी और तुमने...?'' पर जवाब मिलता है - ''तुम्हारी तबीयत देखने आई थीं या चरने? आते ही तबीयत का तो पूछा नहीं - सोफा कब लिया, कितने का लिया, कहां से लिया और हम भी लेंगे की पंचायत करने बैठ गईं। हम भी जा चुके हैं तीन बार उनके यहां। स्टेशन पर बिकने जैसी चाय के साथ इत्ता भी खिला दिया होता तो उनके पांव धोकर पी लेती।''

नाश्ता अपने आफ्टर इफेक्ट्स छोड़ जाता है। अतिथि अपने रास्ते लग जाते हैं, पत्नी मोबाइल लेकर कोप भवन में चली जाती है। बिस्कुट अपनी मांद में घुस जाते हैं। पति, झुंझलाहट मिटाने छत पर जाकर सुट्टे मारने लगता है। जबकि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

शिक्षा

डॉ. ज्योति सिडाना

शिक्षा का बाजारवाद या बाजारवाद की शिक्षा

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर तैयार एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में आत्महत्या के मामले हर साल 2 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं. जबकि छात्रों में आत्महत्या के मामलों की दर सालाना 4 प्रतिशत से बढ़ी. छात्रों की आत्महत्या के कई सारे मामलों को दर्ज भी नहीं किया जाता जो दिखाता है कि ये समस्या कितनी गंभीर हो रही है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले एक दशक में 24 साल तक के व्यक्तियों की आबादी 58.2 करोड़ से घटकर 58.1 करोड़ हो गई है, जबकि इसी दौरान छात्रों की आत्महत्या के मामले 6,654 से बढ़कर 13,044 हो गए हैं. यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 15 से 24 साल का हर 7 में से 1 व्यक्ति खराब मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहा है.

शिक्षा के बाजारवाद के घातक परिणाम अब नक़ल और पेपर लीक की घटनाओं के रूप में सामने आने लगे हैं। देश के विभिन्न राज्यों राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार में पेपर लीक और नक़ल के ऐसे अनेक मामले सामने आते रहे हैं। राजस्थान में 2015 से 2023 के बीच विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की 14 घटनाएं सामने आईं, गुजरात में पिछले सात वर्षों में 14 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 2017 से 2024 के बीच नौ परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। संभवतः यह एक बड़ी वजह है देश में बेरोजगारी और अपराधों की संख्या में वृद्धि की। भारत में पिछले सात सालों में पंद्रह राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं जिनमे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं और बोर्ड परीक्षाएं शामिल हैं। एक खबर के अनुसार पेपर लीक से 1.7 करोड़ अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। यह सिलसिला यही नहीं थमा इसके बावजूद भी नीट-यूजी 2024 की परीक्षा के पेपर लीक की खबर ने विद्यार्थियों में रोष उत्पन्न कर दिया। वैसे ही सिस्टम की लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण अधिकांश भर्ती परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो पाती, अगर कभी समय पर परीक्षाओं की समय सारणी घोषित हो भी जाएं तो किसी न किसी अपरिहार्य कारण से परीक्षा तिथि स्थगित हो जाती है। और तो और अगर परीक्षा हो भी जाए तो अगले दिन सुनने को मिलता है कि पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द की जाती है। एक विद्यार्थी जो सालों की मेहनत के बाद भर्ती परीक्षाओं में सफलता की उम्मीद के साथ पहुँचता है अचानक उसके सपने और उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। परीक्षा होने ना होने की कशमकश में कई युवाओं की तो सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने की उम्र ही निकल जाती है। और पारिक्षाओं व उनके परिणाम के इंतजार में ये युवा विद्यार्थी अन्य क्षेत्रों में भी अपना भविष्य नहीं अजमाते और परिणामस्वरुप बेरोजगारी, अपराध, हिंसा, गरीबी जैसी समस्याएँ दिन प्रतिदिन बढने लगती हैं। आखिर इन अव्यवस्थाओं के लिए कौन जिम्मेदार है समाज, राज्य या उसकी सहायक संस्थाएं या फिर स्वयं विद्यार्थी।

इस समूचे प्रकरण से जुड़े कुछ और पक्षों की चर्चा भी जरूरी है। परीक्षा से पूर्व प्रश्नपत्र का आउट हो जाना, प्रश्नपत्र तैयार करने वाले शिक्षकों पर दबाव डालकर महत्वपूर्ण प्रश्नों के नाम पर प्रश्नपत्रों का परिचय प्राप्त कर लेना, परीक्षा पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों तक पहुँचने की कोशिश और उन पर अनेक दबाव डलवाकर या डालकर उत्तीर्ण होने का प्रयास, अनेक विश्वविद्यालयों में प्री.पीएच.डी कोर्सवर्क का

कागजों में संचालित होना, पीएच.डी की उपाधि में विभिन्न पुस्तकों और शोध ग्रंथों से विषयवस्तु चुराकर उपाधि प्राप्त करने की कोशिश वे पक्ष हैं जो फर्जी डिग्री को कई भागों में बाँट देते हैं जिसमें पैसा देकर प्राप्त की गई फर्जी डिग्री और नकल करके प्राप्त की गई (फर्जी) डिग्री प्रमुख है। इस पूरे संचालन में राजनीति-प्रशासक-शिक्षक-विद्यार्थी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने वाले व्यवसायी/उद्योगपतियों का गठबंधन सक्रि है। सवाल यह है कि शिक्षा को परीक्षा के साथ जोड़ना और डिप्लोमा, प्रमाणपत्र एवं डिग्री को नौकरी एवं अपनी उपलब्धियों को अभिव्यक्त करने का मापक बना लेना वे पक्ष हैं जो भारतीय शिक्षा प्रणाली की विसंगतियों को दर्शाते हैं। यह गठजोड़ पता नहीं कहाँ रूकेगा? नकल और फर्जीवाड़े का यह बाजार किस तरह की युवा कार्यबल (वर्कफोर्स) को विकसित कर रहा है यह किसी से छिपा नहीं है।

यू.पी.एस.सी के प्रश्नपत्रों का आउट होना, राज्यलोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्रों का बाहर आना, सेकेंडरी परीक्षा में किसी एक ही विद्यालय के 17 बच्चों का मेरिट में आना और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एआईपीएमटी की परीक्षा को निरस्त कर देना, वे उदाहरण है जो दर्शाते हैं कि शिक्षा रूपी कुएं में इतनी भांग मिला दी गई है कि उसमें से जो भी निकल कर बाहर आ रहा है उसे लोग नशेड़ी के रूप में देखने लगे हैं। अब तो यूजी नीट 2024 की परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। 67 विद्यार्थियों को 720 में 720 अंक मिलने पर भी सवाल उठ रहे हैं और इनमें से छह अभ्यर्थी हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से हैं। संदेह का यह विस्तार देश के विकास के लिए चुनौती है क्योंकि इन सबमें अधिकांशतः वे लोग सम्मिलित हैं जिन्हें हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में प्रस्तुत करते हुए खुद को गौरवांवित महसूस करते हैं।

देश को केवल तकनीकी विकास की राह पर आगे बढ़ाकर क्या प्रगति और सम्पन्नता प्राप्त की जा सकती है संभवतः ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जरुरी है कि राज्य और प्रशासन देश में तकनीकी विकास के साथ साथ बच्चों और युवाओं के मानसिक व शारीरिक विकास पर भी चिंतन करें कि कैसे इस नई पीढ़ी को समाजीकृत और शिक्षित किया जाए ताकि सफलता प्राप्त करने के लिए वे नक़ल का सहारा ना ले अपितु अपने परिश्रम और बौद्धिक क्षमता पर भरोसा रखे। हाल ही में नीट-यूजी और यूजीसी- नेट परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच के बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ ये कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था। इस कानून में परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। लेकिन दुखद यह है कि किसी भी समस्या को केवल कानून बनाकर हल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हो सकता तो अब तक सभी समस्याओं का हल निकल आया होता।

दिसंबर 2022 में रीट पेपर लीक होने पर हनुमानगढ़ के एक युवक ने कीटनाशक पीकर जान दे दी उसने सुसाइड नोट में लिखा था, सॉरी पापा मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। परिवारी जनों के अनुसार रीट के पेपर में उसके 150 में से 135 नंबर आने का अनुमान था। रिजल्ट आता तो उसका सिलेक्शन पक्का था लेकिन दुर्भाग्य था कि पेपर लीक हो गया। उससे पहले साल में वनपाल का पेपर भी दिया था जो क्लियर हो गया था लेकिन वो पेपर भी लीक हो गया। लगातार दो साल पेपर लीक से डिप्रेशन में चला गया था। दूसरी घाटना यूपी के कन्नौज की है जहाँ 27 साल के बृजेश ने अपनी बीएसई की डिग्री जला दी। और अपनी बहन का दुपट्टा उठाया और उसे गले से लपेट कर फंदा लगा लिया। वह सात साल से यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहा था लेकिन पेपर लीक हो गया और परीक्षा कैंसिल हो गई। और उसने मौत को गले लगा लिया।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर तैयार एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में आत्महत्या के मामले हर साल 2 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं। जबकि छात्रों में आत्महत्या के मामलों की दर सालाना 4 प्रतिशत से बढ़ी। छात्रों की आत्महत्या के कई सारे मामलों को दर्ज भी नहीं किया जाता जो दिखाता है कि ये समस्या कितनी गंभीर हो रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले एक दशक में 24 साल तक के व्यक्तियों की आबादी 58.2 करोड़ से घटकर 58.1 करोड़ हो गई है, जबकि इसी दौरान छात्रों की आत्महत्या के मामले 6,654 से बढ़कर 13,044 हो गए हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 15 से 24 साल का हर 7 में से 1 व्यक्ति खराब मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहा है।

यह कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिससे निजात नही पाया जा सकता बस जरुरत है एक सुनिश्चित और कठोर रणनीति बनाने की। पेपर लीक मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषियों को तुरंत बिना किसी देरी के सजा का प्रावधान हो। ऐसे ममलों को गंभीरता से लिया जाए इनमे किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी के बचाव का प्रयास नही होना चाहिए भले ही अभियुक्त कितना ही ताकतवर हो या किसी कुलीन परिवार से सम्बन्ध रखता हो।

अधिकांश मामलो में यह देखा गया है कि पेपर लीक के जाल में सम्बद्ध संस्था के नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक के अधिकारीयों और कर्मचारियों के शामिल होने के साक्ष्य सामने आते हैं और जाँच समितियां अपनी रिपोर्ट देने में लम्बा समय लगा देती हैं, परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं, नई परीक्षा की तिथि की घोषणा के इंतजार में विद्यार्थियों की नौकरी की उम्र निकलने लगती है और निराशा व तनाव में आकर वे दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। कहते हैं कि शिक्षा का मकसद है एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना, पर क्या वास्तव में हम ऐसा कर पाए हैं, क्या वास्तव में एक सुशिक्षित और सभ्य समाज का निर्माण कर पाए हैं गहन चिंतन का विषय है. किसी ने सच ही कहा है यह जो जिंदगी की किताब है यह किताब भी क्या किताब है। कहीं इक हसीं सा ख़्वाब है कहीं जानलेवा अजाब है।

राजनीति

अनिल ठाकुर

लेखक स्तम्भकार हैं।

हरियाणा में बीजेपी की जीत के मायने

बीजेपी का हरियाणा की जीत से अति उत्साहित होना स्वाभाविक है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा ऐसा पहला राज्य था, जहां उसकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। आरक्षण, जातिगत जनगणना, किसान, जवान, जाट फैक्टर जैसे मुद्दे हरियाणा में विपक्ष के पक्ष में उतने ही असरकारक हो सकते थे, जितने यूपी में। हरियाणा में सत्ता के विरुद्ध नाराजगी भी एक महत्वपूर्ण कारक था। चुनाव के छह माह पूर्व मुख्यमंत्री के बदलाव ने इस धारणा को मजबूत बनाया। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों ने कांग्रेस की इस सोच को मजबूत किया। यही आकर कांग्रेस भूल कर बैठी। उसके नेता राहुल गांधी चुनाव संचालन अपने चाटुकार नेताओं के भरोसे छोड़ विदेश यात्रा पर प्रस्थान कर गए। वहां उनकी भारत विरोधी विदेशी नेताओं से मुलाकात, आरक्षण समाप्त करने एवम मुस्लिम तुष्टिकरण के पक्ष वाले बयानों का विपरित असर हरियाणा के मतदाताओं पर हुआ। कांग्रेस के दो प्रमुख नेता हुड्डा एवम शैलजा के बीच वर्चस्व की लड़ाई एवम दलितों के अपमान ने आग में घी का काम किया।

इन दिनों मतदाता ज्यादा चतुर हो गया है, एक्जिट पोल सर्वेक्षण में भी वह मीडिया के सामने अपने पत्ते नही खोलता। लोकसभा एक्जिट पोल के आंकड़े इसकी पुष्टि करते है। हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान के लिए हार के कारणों पर आत्ममंथन के अतिरिक्त अब कुछ बचा नही है, अगर बीजेपी आने वाले चुनावों में इस प्रदर्शन को दोहराना चाहती है तो उसे वास्तविकता के धरातल पर मूल्यांकन करना होंगा। यह बात गौर करने लायक है कि कई राजनीतिक विश्लेषक मानते है कि कांग्रेस जीती हुई बाज़ी को हार तो बीजेपी हारी हुई बाज़ी को जीत में बदल देती है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी विधान सभा चुनावों में इस प्रदर्शन को दोहरा पायेंगी? इस पर कुछ कहने से पहले हरियाणा के नतीजों से जो प्रमुख बातें निकल कर आई है उन्हे समझना जरूरी है -

1. किसी भी पार्टी का केंद्रीय (core) मतदाता किसी एक मुद्दे पर हमेशा एकमत नही होता।
2. केंद्रीय नेतृत्व या कोई एक चेहरा विधान सभा चुनावों में बहुत ज्यादा प्रभावकारी नही रह गया है।
3. सिर्फ लोक लुभावन घोषणाओं या पैकेज के सहारे मतदाता को लुभाया नही जा सकता।
4. सत्ता, संगठन एवम कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य अति महत्वपूर्ण है।
5. क्षेत्रीय नेतृत्व के मजबूत, हाईकमान के विश्वासपात्र होने के अतिरिक्त, संगठन और कार्यकर्ताओं का उस पर विश्वास अति आवश्यक है ।
6. गठबंधन के अन्य साथियों को उचित प्रतिनिधित्व देना निहायत जरूरी है।

यदि इन बिंदुओं के मद्देनज़र आकलन करें तो अभी बीजेपी को राज्य चुनावों में अपनी रणनीति में बहुत परिवर्तन करना होंगा। महाराष्ट्र में हरियाणा चुनाव नतीजों के पहले तक महा आघाड़ी गठबंधन थोड़ा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था। लेकिन हरियाणा की हार से शिवसेना (उद्धव) गुट की उद्धव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग को बढ़ावा मिला। ऐसे में कांग्रेस किस हद तक समझौता करेंगी एवम शरद पंवार की भूमिका पर सारा दारोमदार होगा। लोकसभा चुनाव में शरद पंवार की पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे अधिक होने से वे सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने की योजना बना रहे हो तो आश्चर्य नही होना चाहिए। शरद पंवार अपने पत्ते अंतिम समय तक नहीं खोलते। अजीत पंवार के बयानों से उनके घर वापसी के संकेत से शरद पंवार का पक्ष और मजबूत हुआ है। कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में अभी कोई मजबूत नेता नहीं है एवम राहुल गांधी सावरकर के बारे में अनेक बार विवादास्पद बयान देकर महाराष्ट्र में अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके है। विवाद सिर्फ महा आघाड़ी में हो ऐसा नहीं है, महायुति सरकार में शिवसेना (शिंदे) के एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री है। लोकसभा चुनाव में अपने दल का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने से इस चुनाव में वे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में मैदान में उतरना चाहेंगे। दोनों गठबंधन में सबसे डांवाडोल स्थिति अजीत पंवार की है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन एवं उनकी पत्नी की हार ने महायुति एवम पंवार परिवार दोनो में उनकी स्थिति को कमजोर किया। मुस्लिमों को टिकिट देने का बयान से उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाने का प्रयास किया है, लेकिन हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी पर इसका असर होगा ऐसा नहीं लगता। वे महायुति से पलायन भी कर जाते है तो बीजेपी और शिवसेना (शिंदे) के लिए राहत होगी। मगर यहां भी मुख्यमंत्री पद की समस्या का हल इतना आसान नहीं है। हरियाणा में हुड्डा एवम शैलजा विवाद कांग्रेस की हार का एक प्रमुख कारण रहा, इसलिए बीजेपी को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। यूपी एवम महाराष्ट्र में किसान, आरक्षण, जातिगत जनगणना के मुद्दे ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया था।

मराठा आरक्षण को लेकर जरांगे बार बार सरकार के लिए परेशानियां खड़ी कर रहे है। ऐसे में क्या बीजेपी हरियाणा की तरह हिंदू वोट बैंक को एक कर पाने में सफल होगी, नतीजे बहुत कुछ इस पर निर्भर करेंगे। हरियाणा चुनाव में संघ ने इस बार सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन क्या इसे संघ एवम मोदी के बीच विवाद की समाप्ति मान लिया जाय? नागपुर में मुख्यालय होने से संघ का महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रभाव है, इसलिए चुनाव में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होंगी । शिंदे ने महिलाओं के लिए आर्थिक योजना लागू कर महायुति के पक्ष को मजबूत बनाया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद एवं सीट बंटवारा ऐसे विषय है, जिनका निर्विवाद निपटारा महायुति के लिए लाभदायक होंगा। ऐसे में दोनों गठबंधन के लिए चुनौती एक दूसरे से कम साथी दलों से ज्यादा है । समझदारी और संयम से व्यर्थ की बयान बाजी से बचते हुए जो गठबंधन अपने अंदर की गांठ को सुलझा लेगा सफल वही होगा।

महाराष्ट्र के अलावा यूपी उपचुनाव नतीजे बीजेपी एवम इंडी गठबंधन की आगे की राजनीतिक दिशा तय करेंगी। इन उपचुनाव नतीजों का राज्य सरकार के अस्तित्व पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं होगा, मगर ये योगी की आगे की राजनीतिक यात्रा का भविष्य तय करेंगे। यूपी में बीजेपी से ज्यादा योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। संघ और केंद्रीय सत्ता के बीच कितना तालमेल हुआ है, यह भी नतीजों से सामने आ जायेगा। इसी तरह इन नतीजों का प्रभाव सपा प्रमुख अखिलेश से ज्यादा राहुल गांधी की राजनीति पर होंगा। अखिलेश ने कांग्रेस से बिना चर्चा किए उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर इसके संकेत दे दिए है। सार रूप में कहा जाए तो इंडी गठबंधन का भविष्य महाराष्ट्र और यूपी के नतीजों पर टिका है तो बीजेपी के लिए मोदी कितने महत्वपूर्ण है, यह भी ये नतीजे तय करेंगे।

मुद्दा

रामलखन गुर्जर

स्लम बस्ती में रहने वालों को भी मिले स्वास्थ्य सुविधाएं

विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश भारत में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. यद्यपि पिछले कुछ दशकों में इसमें काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में और अधिक काम करने की आवश्यकता है. वर्ष 2024-25 के बजट में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 90,958 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है. जो पिछले वर्ष 2023-24 के बजट में आवंटित किये गए 89,155 करोड़ रुपए से दो फीसदी अधिक है. इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में भी बजट में वृद्धि की गई है. वर्ष 2023-24 के 2,980 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष दस फीसदी से अधिक की वृद्धि करते हुए 3,301.73 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं. इसके बावजूद न केवल ग्रामीण, बल्कि शहरी क्षेत्रों में आबाद स्लम बस्तियों के लोगों को भी स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित स्लम बस्ती 'रावण की मंडी' इसका एक उदाहरण है. जहां अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुंच नहीं हो पा रही है.

जयपुर शहर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन रावण की मंडी जैसे शहर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, यहां रहने वाले समुदायों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने का साफ पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इस संबंध में बस्ती में रहने वाली 47 वर्षीय लालिमा देवी बताती हैं कि 'यहां न तो स्वास्थ्य केंद्र है और न ही डॉक्टरों या नर्सों की सुविधा उपलब्ध है. प्रसव, टीकाकरण और अन्य चिकित्सा आवश्यकताओं की देखभाल के लिए भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है. परिणामस्वरूप, यहां गर्भवती महिलाओं और जन्म लेने वाले बच्चों की मृत्यु दर अधिक है.' वह बताती हैं कि यहां रहने वाले किसी भी परिवार को पीने का साफ़ पानी भी नहीं मिल पाता है. अक्सर दूषित जल पीने के कारण बच्चे बीमार हो जाते हैं. लेकिन किसी प्रकार का पहचान पत्र नहीं होने के कारण उनका सरकारी अस्पताल में इलाज भी नहीं हो पाता है. वहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण माता-पिता उन बच्चों का इलाज किसी निजी अस्पताल में कराने में सक्षम नहीं होते हैं. इस बस्ती में मलेरिया, दस्त और सांस संबंधी बीमारियां आम हैं क्योंकि यहां के लोग गंदगी और कचरे के बीच रहने को मजबूर हैं.

राज्य सचिवालय से करीब 12 किमी दूर स्थित इस बस्ती में 40 से 50 झुग्गियां आबाद है. जिसमें लगभग 300 लोग रहते हैं. इस बस्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की बहुलता है. जिसमें जोगी, कालबेलिया और मिरासी समुदाय प्रमुख रूप से शामिल है. प्रति वर्ष विजयदशमी के अवसर पर रावण दहन के लिए यहां रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले तैयार किए जाते हैं. जिसे खरीदने के लिए जयपुर के बाहर से भी लोग आते हैं. इसी कारण इस बस्ती को रावण की मंडी के रूप में पहचान मिली है. विजयदशमी के अलावा साल के अन्य दिनों में यहां के निवासी आजीविका के लिए रद्दी बेचने, बांस से बनाये गए सामान अथवा दिहाड़ी मज़दूरी का काम करते हैं. शहर में आबाद होने के बावजूद इस बस्ती में मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है. इनमें स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है. यहां महिलाओं और बच्चों में स्वास्थ्य और पोषण की कमी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है. यहां अधिकतर महिलाएं विशेषकर गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चे कुपोषण का शिकार हैं तो वहीं अन्य लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार होते हैं.

बस्ती की 38 वर्षीय लीला देवी बताती हैं कि वह कालबेलिया समुदाय से हैं. जिसे घुमंतू और खानाबदोश जनजाति के रूप चिन्हित किया जाता है. घुमंतू होने के कारण उनका कोई स्थाई ठिकाना नहीं होता था. ऐसे में उन लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी कभी कोई प्रमाण पत्र नहीं बन सका है. हालांकि अब वह लोग पिछले 8 वर्षों से रावण की मंडी में रह रहे हैं. इसके बावजूद अब तक उनका या उनके परिवार में किसी का स्थाई निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है. इसके कारण सरकारी अस्पताल में उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती है. जब वह सरकारी अस्पताल जाती हैं तो उन्हें यह कह कर लौटा दिया जाता है कि उनका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. उन्हें निजी अस्पताल में जाने को कहा जाता है. जहां इलाज काफी महंगा होता है. लीला के पति 42 वर्षीय काला राम कहते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड में यह बस्ती अधिकृत नहीं हैं. इसलिए अधिकारी यहां पीने का साफ़ पानी या अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त करते हैं. वह बताते हैं कि बस्ती के कुछ परिवार आपस में चंदा इकठ्ठा करके प्रति सप्ताह पानी का टैंकर मंगवाते हैं ताकि परिवार को पीने का साफ़ पानी मिल सके. लेकिन पानी ख़त्म हो जाने पर गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है.

एक अन्य महिला गुड़िया देवी बताती हैं कि यहां आसपास फैले कूड़े-कचरे के कारण लोगों में दाद, खाज और खुजली जैसी बीमारियां फैली रहती हैं. बरसात के दिनों में लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लोगों को संक्रामक बीमारियों का खतरा है. गुड़िया के अनुसार यहां के लोगों के पास शौच के लिए भी विशेष सुविधा नहीं है. हर घर शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है जो पानी की विशेष सुविधा नहीं होने के कारण अक्सर गंदा रहता है. इसका सबसे बुरा प्रभाव महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है. गंदगी के कारण वह जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं. वहीं एक 17 वर्षीय किशोरी पूजा बताती है कि उसने स्कूल में दिए जाने वाले आयरन की गोली के बारे में सुना है, इससे किशोरियों का स्वास्थ्य ठीक रहता है. लेकिन घर में छोटे भाई बहनों को संभालने के कारण उसका स्कूल छूट चुका है. वह बताती है कि बस्ती में स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां देने कभी कभी स्वयंसेवी संस्थाओं की दीदियां आती हैं.

एक अन्य महिला विमला कहती हैं कि 'इस बस्ती में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है. न तो बिजली का कनेक्शन है और न ही पीने का साफ़ पानी उपलब्ध है. हमें ऐसे ही हालात में जीना होगा.' वह कहती हैं कि यहां रहने वाली महिलाओं और किशोरियों का न तो स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ है और न ही अस्पताल में उन्हें स्वास्थ्य की कोई सुविधा उपलब्ध हो पाती है. वहीं बच्चों को भी समय पर टीका उपलब्ध नहीं हो पाता है. वहीं 35 वर्षीय शारदा कहती हैं कि 'मैं 8 वर्षों से यहां रह रही हूं. यहां रहते हुए मैंने दो बच्चों को जन्म दिया है. लेकिन किसी प्रकार का दस्तावेज़ नहीं होने के कारण सरकारी अस्पताल में मुझे एडमिट नहीं किया गया. जिसकी वजह से मेरी दोनों डिलेवरी घर पर ही हुई है. गर्भावस्था के दौरान भी मुझे स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा नहीं मिल सकी है.' वह कहती है कि हम दैनिक मज़दूर हैं. रोज़ाना मज़दूरी करने निकल जाते हैं. हमें दस्तावेज़ बनाने की पूरी जानकारी भी नहीं है. इसलिए आज तक हमारे पास कोई कागज़ नहीं बना है. जबकि सरकारी अस्पताल जाते हैं तो वहां दस्तावेज़ या प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं. इसीलिए इलाज ही नहीं बल्कि प्रसव भी घर पर ही करवाने पड़ते हैं.

हालांकि सरकार की ओर से स्वास्थ्य संबंधी कई कार्यक्रम और योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसी योजनाएं रावण की मंडी जैसी स्लम बस्तियों तक ठीक से लागू नहीं हो पाती हैं. जिसके कारण यहां रहने वाले लोग बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं. इसे यहां बेहतर बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की जरूरत है, जहां प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी भी उपलब्ध हों. वहीं केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की किये जाने की आवश्यकता है. दूषित जल आधी बीमारियों की जड़ होती है. ऐसे में यहां पीने का साफ पानी और स्वच्छता उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपाय करने की जरूरत है. इससे न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होंगी बल्कि बीमारियों को फैलने से भी रोका जा सकेगा. इस काम में सरकार और प्रशासन के साथ साथ स्थानीय सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. आखिर स्लम बस्ती में रहने वालों को भी अन्य लोगों की तरह स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का पूरा अधिकार है, जो उन्हें हर परिस्थिति में उपलब्ध कराई जानी चाहिए. (चरखा फीचर्स)

विषय शिक्षकों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

बैतूल। जेएच महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में स्कूल शिक्षा से संबंधित जिले की विभिन्न शालाओं के प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य एवं विषय शिक्षकों के साथ प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उनकी प्रगति की समीक्षा की गई। जिसमें वर्तमान सत्र में अब तक संपन्न बेसलाइन, मिडलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट एवं त्रैमासिक परीक्षा के परिणामों पर चर्चा कर अर्धवार्षिक परीक्षा के अतिरिक्त, शैक्षणिक सत्र में शेष रहे दिनों में शिक्षण की गुणवत्ता उन्नयन किए जाने के लिए अपनाई जाने वाली कार्य योजना पर विस्तार से जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ अनिल कुशवाहा एवं सहायक आयुक्त आजाक विभाग श्रीमती शिल्पा जैन ने समीक्षा के साथ परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए प्राचार्य एवं शिक्षकों का उत्साहवर्धन करते हुए शैक्षणिक सत्र के आरंभिक दिनों में विभिन्न कारणों से शैक्षणिक गतिविधियों की अपेक्षित गति प्रभावित होने की चर्चा की। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम लाए जाने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया गया। जिला परियोजना समन्वयक जीएल भनारिया ने सर्वेक्षण की तैयारी के बारे में बताया गया। विभागीय अधिकारी सुबोध शर्मा द्वारा राष्ट्रीय परख सर्वे, अपार आईडी निर्माण, समग्र छात्रवृत्ति, निशुल्क साइकिल योजना, अतिथि शिक्षक व्यवस्था इत्यादि पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिले की प्रगति और अधिक सुदृण किए जाने के लिए प्रेरित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अनिल कुशवाहा ने शालाओं को डिग्री प्रदान किए जाने का स्थान मात्र न बनाए रखने के बजाय छात्र-छात्राओं की प्रतिभा को निखारने के लिए उन्हें उचित संसाधन उपलब्ध कराते हुए उत्कृष्ट भविष्य के निर्माण संबंधी अपनी रूपरेखा को आगे बढ़ाया, सत्र पर्यंत एवं ग्रीष्म अवकाश में जेईई, नीट संबंधी शासकीय शिक्षकों के सहयोग से संचालित निशुल्क कोचिंग के आयोजन की रूपरेखा के साथ आने वाले दिनों की रणनीति के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में विकासखंड शिक्षा अधिकारी जीसी सिंह, एनए प्रहलादी, जिला उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य सत्येंद्र उदयपुरे, शासकीय कन्या गंज शाला के प्राचार्य श्री लिल्हारे, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

भाजपा नेता सुसाइड केस: पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

बैतूल। सारणी क्षेत्र के बहुचर्चित भाजपा नेता रविन्द्र देशमुख के सुसाइड केस में आरोपी बनाये गये भाजपा नेता सहित पांच लोगों की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। एडीजे कोर्ट में इसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आवेदन निरस्त कर दिया है। पीडित पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल महाले ने जमानत देने का विरोध करते हुए तर्क रखा कि गंभीर अपराध है। बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और पैसे की उगाही की गई। पहले भी इसी तरह के मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। उसमें आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल गई थी। दोबारा इसी तरह का अपराध किया गया है। इस वजह से उनकी पूर्व में दी गई अग्रिम जमानत भी निरस्त की जाए। न्यायालय में शासन की ओर से लोक अभियोजक नितिन मिश्रा और पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल महाले ने अपना पक्ष रखा। न्यायालय में आरोपी अभिषेक साहू, रंजीत सिंह, नाजिया बानो, करण सूर्यवंशी, प्रकाश शिवहरे को अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए याचिका दायर की गई थी। गौरतलब रहे कि 7 अक्टूबर को भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रविंद्र देशमुख ने बागडोना में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने इस मामले में आरोपी रंजीत सिंह, प्रकाश शिवहरे, दीपक शिवहरे, प्रमोद गुप्ता, अभिषेक साहू, मोहम्मद नसीम रजा, शमीम रजा, नाजिया बानो, करण सूर्यवंशी, और भोला सिंह उर्फ रामनारायण सिंह को आरोपी बनाया था। इन सभी पर मृतक रविंद्र देशमुख को पैसों के लिए मानसिक प्रताड़ना देने और समाज में उसकी छवि खराब करने की धमकी देकर दबाव बनाने का आरोप है। हालांकि इनमें से दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

घर से लापता बालक का शव तालाब में मिला, पुलिस कर रही जांच

बैतूल। घर से लापता बालक का शव तालाब में मिला। बालक गुरुवार से लापता था। एसडीईआरएफ के दल ने तलाश के बाद शव पानी से बाहर निकाला। घटना कोतवाली थाना इलाके के मंडई बुजुर्ग की है। सोनाघाटी पुलिस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक वहीद खान के मुताबिक

मृतक आयुष पिता छुट्टन धुर्वे (12) गुरुवार दोपहर से लापता था। उसके माता-पिता सिंगाजी दर्शन के लिए गए हुए हैं। घर में मौजूद अन्य परिजनों ने जब उसकी तलाश शुरू की तो गुरुवार शाम बालक की चप्पल कपड़े और साइकिल तालाब के किनारे खड़ी मिली। पुलिस ने घटना के संदर्भ में एसडीआरएफ की टीम को बालक की तलाश के लिए सूचना दी। रात होने की वजह से यहां रेस्क्यू अभियान नहीं चलाया जा सका। शुक्रवार सुबह एसडीईआरएफ की टीम प्लाटून कमांडर सुनीता पंद्रे के नेतृत्व में तालाब पर पहुंची और तलाश अभियान चला कर बालक का शव तालाब से बाहर निकाला गया है। जिसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल बैतूल में बालक के शव का परीक्षण करवाया है। जिसके बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। यह बालक कक्षा छठवीं का छात्र था। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

बैंक द्वारा ठगी से बचने चलाया जागरूकता अभियान

बैतूल। स्टेट बैंक मुख्य शाखा के द्वारा शुक्रवार को ढोंडवाड़ा स्कूल में शिक्षकों, विद्यार्थियों व ग्रामीणों को साइबर सिक्योरिटी के विषय में विस्तार से बताया। बैंक के मैनेजर अरविंद सिंह व दीपक चढोकार ने संबोधित करते हुए बताया कि किसी भी अनजान व्यक्ति को

ओटीपी, पासवर्ड और बैंक खाते की जानकारी न दें। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति का वीडियो कॉल नहीं रिसीव करें। बैंकर्स अलकेश झपाटे व अंकित परते ने कहा कि इस प्रकार यह अभियान चलाकर लोगों में जन जागृति लाना ही हमारा उद्देश्य है। जिससे लोग ठगी से बच सकें। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक मदनलाल डढोरे ने करते हुए कहा कि साइबर क्राइम के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने की महत्ती आवश्यकता है। जिससे ठगी से बचा जा सके। इस अवसर पर पालक स्कूल स्टॉफ, छात्र-छात्राएं व ग्रामीण जन मौजूद थे।

मरम्मत पर हर साल खर्च हो रहे लाखों रूपये, फिर भी हालात जस की तस

सड़कों की क्षमता 20 टन वजन की, गुजर रहे दो-तीन गुना वजनी वाहन, इसलिए सड़क जल्द हो रही खराब

संजय द्विवेदी, बैतूल। शहर की सडक़े बारिश के बाद छलनी हो गई। सडक़ों पर गड्ढों से परेशान वाहन चालक इनके सुधार के लिए आस लगाए बैठे हैं। इन सडक़ के छलनी होने का एक कारण यह भी है कि नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी विभाग 15-20 टन वजन क्षमता वाली सडक़ों का निर्माण कराती है, लेकिन सडक़ों पर क्षमता से दो-तीन गुना वजनी वाहन गुजर रहे है। जिसके कारण शहर की सडक़ इन भारी भरकम वाहनों के सामने टीक ही नहीं पा रही है और भारी ट्रैफिक के कारण सडक़े पिचक रही है। दरअसल शहर में 21 किमी मेन रोड है। इसमें से अधिकांश रोड नगरपालिका ने पीडब्ल्यूडी से ले लिया है। अब इन सडक़ों का निर्माण और मरम्मत नगरपालिका करती है। नगरपालिका जो सडक़े बनाती है, उसकी वजन सहने की क्षमता 20-25 टन तक होती है, लेकिन सडक़ों पर 30-40 टन से अधिक भार वाले वाहन गुजरते है। जिससे सडक़े पिचक जाती है या टूटकर बिखर जाती है। गंज सडक़, रेलवे स्टेशन सडक़, गंज से गुरूद्वारा होते हुए चौपाटी वाली सडक़ तो कई जगहों से दब गई है, जिस पर वाहन चलाते समय हिचकोले लगते है। इन सडकों की मरम्मत कराई भी जाती है, तो अधिक वजन वाले डंपरों या वाहनों की वजह से यह लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। नजीता वाहन चालकों को खराब सडक़ो पर आवागमन करना पड़ता है। ऊपर से शहर का सामान्य यातायात भी प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ती है।

यातायात के दबाव को ध्यान में रखकर नहीं बनती सड़कें - नपा ने कायाकल्प अभियान के तहत सडके बनाई है, लेकिन यह सडक़े भी गुणवत्ताविहिन कार्य की भेंट चढ़ गई। कॉलेज चौक से गंज जाने वाली रोड जगह-जगह से दब गई है। इनकी मरम्मत कराई भी जाती है तो सडक़े लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। अधिकारियों ने बताया सडक़ों के गड्ढों को भरा जायेगा, लेकिन कुछ ही समय के बाद भारी वाहनों के वजन से गड्ढे उभर आते है। शहरी क्षेत्र में कई स्थानों पर डामर की सडक़ पिचकी हुई देखी जा सकती है। जिला अस्पताल से कारगिल चौक जाने वाली सडक़ का हिस्सा इसी तरह अंदर धंसा हुआ है। इसके पीछे मुख्य कारण संबंधित सडक़ों पर यातायात का दबाव है। इस सडक़ पर 24 घंटे यातायात चलता है। जिससे सडक़ जल्द खराब हो गई।

रेत, गिट्टी गिरने के कारण भी सड़कें हो रहीं बर्बाद

ओवरलोड डंपरों के कारण रेत, गिट्टी सडक पर गिरती है। अन्य वाहनों के पहिये में दबने से गिट्टी सडक़ों को भी खराब करती है। रोजाना बड़ी मात्रा में ओवरलोड डंपर शहर में प्रवेश करते है, जिनकी गति भी निर्धारित से अधिक होती है। डंपरों की तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग के कारण सडक़े तो खराब होती ही है, साथ ही हादसों की भी संभावना बनी रहती है। सुबह तडके 5 बजे से देर रात तक सडकों पर डंपरों की मौजूदगी रहती है। जिनकी क्षमता 8-10 टन रेत-गिट्टी की है, लेकिन डंपरों में अतिरिक्त प्लेटे लगाकर दोगुनी रेत, गिट्टी भरकर परिवहन किया जाता है। इससे सड़क बर्बाद हो रही है और सड़क दब रही है, तथा सड़क पर गड्ढे भी होते जा रहे है। जिससे दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे है।

इनका कहना है -

आप जिन सडक़ों का बता रहे है, यदि उनके टैंडर हो चुके है तो वर्कआर्डर जारी करके ठेकेदारों से काम शीघ्र चालू करवाया जायेगा। तेज बारिश के चलते इस कार्य में विलंब हुआ है। बारिश रूकते ही तुरंत कार्य चालू करवाया जायेगा।

- सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

शहर के गुरूद्वारा और कॉलेज रोड पर भारी ट्रॉफिक के चलते सडक़े पिचकने की जानकारी नागरिकों से मिली है। दशहरे के बाद सडक़ की मरम्मत का काम शुरू होना था, लेकिन तेज बारिश के चलते मरम्मत कार्य को कुछ दिन आगे बाड़ना पड़ा। नये सीएमओ ने आज ही ज्वाइंन किया है। कल उनसे चर्चा करके आगे की कार्यवाही के लिए ठेकेदारों से शीघ्र काम चालू करवाया जायेगा।

- श्रीमती पार्वतीबाई बारस्कर, अध्यक्ष, नगरपालिका बैतूल

अंडर-19 राज्यस्तरीय शालेय प्रतियोगिता में बैतूल के खिलाड़ियों ने किया बेहतर प्रदर्शन

नर्मदापुरम टीम का प्रतिनिधित्व कर हासिल किया तीसरा स्थान

बैतूल। अंडर-19 राज्यस्तरीय शालेय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बैतूल के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम नर्मदापुरम को सेमीफाइनल खेलने वाली टीमों के बीच आयोजित मैच जीतकर तीसरा स्थान दिलाया। यह प्रतियोगिता विगत 14 से 18 अक्टूबर तक सतना में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, भोपाल, नर्मदापुरम, सतना सहित अन्य संभागों की टीमों ने भी प्रतिनिधित्व किया था। बॉस्केटबॉल के वरिष्ठ प्रशिक्षक राकेश वाजपेयी ने बताया कि अंडर-19 बॉस्केटबॉल प्रतियोगिता में बैतूल से अश्विनी तिरकी, पराग मांडवीकर, पूर्णोन्द्र दुबे और श्री गौतम ने नर्मदापुरम टीम का प्रतिनिधित्व किया था। इस प्रतियोगिता में बैतूल टीम के मैनेजर रहे प्रशिक्षक सचिन पाल ने बताया कि सेमीफाइनल मैच में नर्मदापुरम टीम ने भोपाल को 5 स्कोर से हराकर जीत हासिल की। सेमीफाइनल में नर्मदापुरम टीम ने जंहा 50 स्कोर बनाया, वंही भोपाल की टीम 45 स्कोर ही बना पाई। इसके पूर्व के मैचों में भी नर्मदापुरम की टीम ने ग्वालियर को 35-07, शहडोल को 40-10, जबलपुर को 39-31 के स्कोर से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। सेमीफाइनल के रोमांचक मेच में बैतूल के खिलाडि़यों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए भोपाल की टीम को शिकस्त दी और तीसरा स्थान हासिल किया। बैतूल के खिलाडियों के उम्दा प्रदर्शन पर बैतूल जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन सहित खेल प्रेमियों ने खिलाडियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

अजमीढ़ देव की शोभायात्रा में उमड़ा जन समुदाय

विधायक डॉ. पंडाग्रे ने कहा- समाज के उत्थान के लिए हर प्रयास होंगे

बैतूल। गुरुवार रात आमला के रतेड़ा रोड स्थित दादाजी मैरिज लॉन में स्वर्णकार समाज के आराध्य अजमीढ़ देव की जयंती धूमधाम से मनाई गई। समारोह में स्थानीय स्वर्णकार बंधुओं ने अपराह्न 4 बजे वृहद शोभायात्रा निकाली, जो, आमला मुख्य बाजार से निकलकर कार्यक्रम स्थल पहुंची। शोभायात्रा का जगह-जगह स्वागत किया गया। शाम को विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे की मौजदूगी में आयोजित समारोह में वृद्धों, समाज की प्रतिभाओं एवं अन्य लोगों का सम्मान किया गया। स्वर्णकार समाज आमला हर वर्ष प्रति वर्ष अजमीढ़ देव की जयंती धूमधाम से मनाते है। यह आयोजन वृहद स्तर पर किया गया। आमला के अलावा अजमीढ़ देव जयंती के कार्यक्रम में बोडखी, खेड़ली बाजार, खानापुर, मोरखा, साईखेड़ा, खेड़ीकोर्ट, आठनेर, सारनी, बैतूल से सैकड़ों की तादात में सामाजिक बंधु पहुंचे थे। शोभायात्रा सोनी प्ले स्कूल इतवारी चौक से शुरु होकर सोनी मोहल्ला, सर्राफा बाजार, पुराना पुलिस थाना मेन रोड, पीर मंजिल चौक, न्यू मार्केट, चारबत्ती चौक से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। शोभायात्रा

का बड़ी तादात में लोगों ने फूलों की बारिश कर जगह-जगह स्वागत किया।

कार्यक्रम में प्रतिभाओं का सम्मान - दादाजी मैरिज लॉन में जयंती कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में स्थानीय बंधुओं को देख डॉ. योगेश पंडाग्रे गद-गद हो गए। उन्होंने कहा कि स्वर्णकार समाज की एकजुटता और बड़ा जनसमुदाय कार्यक्रम में शामिल होना बता रहा है कि समाज कितना आगे बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि समाज के हित के लिए वे हमेशा आगे रहेंगे। सभी लोग उनके लिए जो भी काम कहेंगे, उसे प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। इस दौरान 85 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों और समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम को कुंजबिहारी सिक्केवाल, रूपलाल सोनी, अनिल सोनी, राजेश सोनी, मनोज सोनी मोरखा, डॉ. श्याम सोनी बैतूल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप सोनी और आभार स्वर्णकार समाज के आमला अध्यक्ष लोकेश सोनी ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में जिला मुख्यालय के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु मौजूद थे।

अज्ञात कारणों से बुजुर्ग ने खाया जहर , मौत

बैतूल। अज्ञात कारणों के चलते एक बुजुर्ग ने जहर खा लिया, जिसे उपचार के लिए लाते समय उसकी मौत हो गई। घटना आमला थाना इलाके के ग्राम जामदेही कला की है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जानकारी के अनुसार गंगू पन्द्रम (60) निवासी ग्राम जामदेही कला गुरुवार रात घर में अकेला था। इसी दौरान रात करीब 1 बजे बुजुर्ग ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जब परिचित बुजुर्ग के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुजुर्ग बेसुध हालत में अपने घर में पड़ा हुआ है। इसके बाद उन्होंने बुजुर्ग को गंभीर हालत में पहले आमला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद बुजुर्ग को एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल बैतूल रेफर कर दिया गया था। जब परिजन बुजुर्ग को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने जांच के बाद बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। बुजुर्ग के आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल बुजुर्ग के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

नपा सीएमओ सतीश मटसेनिया ने किया कार्यभार ग्रहण

बैतूल। शुक्रवार सुबह नगरपालिका के नये सीएमओ सतीश मटसेनिया ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। श्री मटसेनिया श्योपुर से स्थानांतरित होकर आए है। नये सीएमओ श्री मटसेनिया ने नगरपालिका पहुंचकर कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर कुछ व्यवस्था में सुधार के लिए भी कहा। पदभार ग्रहण करने के बाद सीएमओ ने नपा अध्यक्ष पार्वती बारस्कर, उपाध्यक्ष महेश राठौर, सभापति आनंद प्रजापति, सभापति रघुनाथ लोखंडे, संतोष भलावी सहित समस्त पार्षदों और अधिकारी-कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सभी पार्षदों से परिचय लिया। उन्होंने पार्षदों से उनकी समस्याएं भी जानी। गौरतलब रहे कि नगरपालिका बैतूल के सीएमओ ओमपाल भदौरिया का स्थानांतरण हो गया है, उनके स्थान पर श्योपुर से स्थानांतरित होकर सतीश मटसेनिया आये है, जिन्होंने शुक्रवार को अपना कार्यभार ज्वाइन किया।

अज्ञात बाइक चालक ने लिफ्ट के बहाने छात्राओं को बैठाया

बाइक नहीं रोकी तो छात्राएं कूदी, जिला अस्पताल में भर्ती

बैतूल। घर से स्कूल जा रही दो छात्राओं को अज्ञात बाइक सवार ने लिफ्ट दी। जब छात्राओं ने बाइक रोकने के लिए कहा तो बाइक सवार ने गाड़ी नहीं रोकी और आगे ले जाने लगा, तभी दोनों छात्राएं बाइक से कूद गई। जिससे दोनों छात्राओं को गंभीर चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह कक्षा 11वीं की छात्राएं बैतूल बाजार स्कूल जा रही थीं। स्कूल जाने में देरी होने के चलते उन्होंने अज्ञात बाइक सवार से लिफ्ट ले ली। छात्राएं बाइक पर बैठ गई और स्कूल जाने लगीं। जब छात्राओं ने बाइक रोकने के लिए कहा तो बाइक सवार आगे जाने लगा। इसी दौरान घबराकर छात्राएं चलती बाइक से कूद गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक सवार ने छात्राओं को नशे से संबंधित कोई पाउडर का सुंघाया था, जिसके बाद वे धीरे-धीरे मदहोश होने लगी। बाइक से कूदने के कारण छात्राओं को गंभीर चोट आई है। तत्काल छात्राओं को उपचार के लिए एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती किया है। घटना के बाद से बाइक सवार युवक फरार है।

सूचना मिलते ही एएसपी कमला जोशी, एसडीओपी शालिनी परस्ते, बैतूल टीआई देवकरण डहरिया, बैतूल बाजार टीआई अंजना धुर्वे जिला अस्पताल पहुंच गए हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है दो बच्चियों के साथ घटित घटना पश्चात उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया किया गया था। बैतूल एसपी निश्चल झारिया ने कहा कि मेरी उन बच्चियों से बात हुई है, उनका स्पष्ट कहना है कि नशे के पाउडर संबंधित कोई बात नहीं हुई है। एसपी ने कहा कि इस मामले में और गहन जांच की जा रही है। मामला नाबालिग बच्चों से संबंधित है और संवेदनशील होने से विस्तृत जांच की जा रही है।

रेलवे कर्मचारियों के लिए शिकायत एवं चिकित्सा जांच शिविर आयोजित

बैतूल/भौरा। नागपुर मंडल मध्य रेलवे के निर्देशानुसार शुक्रवार को डोडरामोहर स्टेशन पर शिकायत सह चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान और उनके स्वास्थ्य की जांच के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, जिसमें कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। इस शिविर में विशेष रूप से कार्मिक विभाग से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान दिया गया, जिसमें कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों, वेतन, वरिष्ठता, एचआरएसएस (ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम) में सुधार, और उम्मीद योजना से संबंधित मुद्दों का समाधान किया गया। कर्मचारियों ने अपने पारिवारिक सदस्यों के विवरण में संशोधन सहित अन्य

प्रशासनिक समस्याओं पर भी चर्चा की, जिनका निपटारा मौके पर किया गया। डोडरामोहर और आसपास के स्टेशनों पर कार्यरत रेल कर्मचारियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा जांच भी शिविर का एक प्रमुख हिस्सा था। नागपुर मंडल से आए विशेषज्ञ चिकित्सक निहार और उनकी टीम ने कर्मचारियों और उनके परिवारों की गहन चिकित्सा जांच की। इस दौरान ब्लड शुगर, रक्तचाप (बीपी), आंखों की जांच और खून की जांच की गई। करीब 50 से 60 रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस स्वास्थ्य जांच में भाग लिया। शिविर में प्रमुख रूप से डोडरामोहर स्टेशन प्रबंधक डीएस परिहार, कल्याण निरीक्षक बैतूल अनिल महाले, नागपुर मंडल के फार्मासिस्ट महेश लांडे और आमला के फार्मासिस्ट रविकांत पडोले, स्वास्थ्य निरीक्षक कैलाश माथनकार आमला, कार्यालय अधीक्षक पलाश नागपुर, और डोडरामोहर के लिपिक ओमप्रकाश दुबे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेलवे मंडल नागपुर द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को विभिन्न स्टेशनों पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिसमें कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करने के साथ ही स्वास्थ्य जांच का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। डोडरामोहर में आयोजित इस शिविर से कर्मचारियों को न केवल उनकी समस्याओं का समाधान प्राप्त हुआ, बल्कि उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच से उन्हें भविष्य में होने वाली समस्याओं से भी बचाव में मदद मिलेगी।

पहाड़िया स्थित कालोनी में हरिनाम संकीर्तन

नर्मदापुरम। दामोदर मास (कार्तिक मास) के विशेष अवसर पर द्वितीय दिवस भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस्कॉन मंदिर परिवार द्वारा पहाड़ियां के निकट स्थित साईं हेवन सिटी कालोनी शिव मंदिर में दीप-दान किया जिसमें बड़ी संख्या में कालोनी निवासियों ने भाग लिया। दीप-दान से पूर्व पहले दामोदर अष्टक का गायन और कालोनी भ्रमण कर कृष्ण भक्तों ने हरिनाम संकीर्तन के जरिए कालोनी वासियों को संकीर्तन में सम्मिलित कर अध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्हें दीप-दान के लिए प्रेरित किया। नगर में इस्कॉन मंदिर परिवार द्वारा किए जा रहे आयोजन और होने वाले कार्यक्रमों सहित श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की काफी चर्चा है।

पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर छात्र-छात्राएं ले रहे प्रशिक्षण.....

संवेदनशील व्यवहार ही महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन दे सकता है : डॉ हंसा व्यास

नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जिले के शासकीय नर्मदा महाविद्यालय में आये दिन छात्र एवं छात्राओं के भविष्य को देखते हुए नवाचार किये जा रहे है इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश टूरिज्म, जिला प्रशासन द्वारा नर्मदापुरम में विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी एवं महिला हेतु सुरक्षित पर्यटन के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण इंडियन ग्रामीण सर्विसेज द्वारा कराया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राचार्य डॉ अमिता जोशी के मार्गदर्शन में एवं डॉ हंसा व्यास द्वारा नर्मदापुरम पर्यटन को प्रमोट करने के लिए विद्यार्थियों को नर्मदापुरम मुख्यालय पर स्थित पर्यटन स्थलों के इतिहास की वृहद जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। उनके द्वारा व्यवहार कौशल एवं सम्प्रेषण कौशल पर विद्यार्थियों से चर्चा की गई साथ ही पर्यटन स्थलों पर गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही पोस्टर, बेग, ब्रोशर, मग, बनाने की भी जानकारी दी जा रही है। जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के पर्यटन प्रबंधक मनोज सिंह ठाकुर ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड एवं जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दने को लेकर लगातार गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। जिससे पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी हो सके एवं महिला हेतु सुरक्षित पर्यटन के लिए महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। प्राध्यापक डॉ कल्पना विश्वास ने पर्यटन का अर्थ और उसका महत्व समझाया कार्यशाला में पैसा एक्ट से अरविंद धुर्वे, इंडियन ग्रामीण सर्विसेज से रोहित सोनवानी, वैष्णवी मांझी, शांति मांझी, मनोज टेकाम, अपूर्वा, धर्मेंद्र, पाखी, अमन मेहरा नवनीत गौर, समीक्षा तिवारी, मेघा मीना, रूक्मणी अहिरवार, मुस्कान, धर्मेन्द्र, अतुल चौहान, अम्बिका राजपूत, पुरूषोतम अहिरवार आदि विद्यार्थी उपस्थित रहे।

वाल्मिकी जयंती पर किया सेवानिवृत्त शिक्षक का सम्मान

देवास। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कृषि उपज मंडी भैसूनी (विजयागंज मंडी) जिला देवास में अजाक्स पेंशनर्स तहसील देवास जिला देवास द्वारा सेवा निवृत्त सम्मान समारोह राधेश्याम राठौर हाई स्कूल प्राचार्य की अध्यक्षता एवं मुख्य अतिथि अजा अजजा सामाजिक समन्वय समिति देवास के संस्थापक मदनलाल जेठवा तथा अजाक्स उज्जैन संभागीय अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी, संभागीय

सचिव बिक्रम सिंह परमार, अजाक्स उज्जैन जिला अध्यक्ष डॉ आर एल परमार, वर्मा के विशेष आतिथ्य में सर्व प्रथम डॉ भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर आयोजित किया गया। जिसमें गत माह में सेवानिवृत्त हुए शिक्षक भेरूलाल चौहान शा.प्रा.वि.ढाबला व शिक्षक गणपतलाल मालवीय शा.मा.वि.नोशराबाद का साफा शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रामलाल सोलंकी, तोलाराम राठौर संस्थापक अध्यक्ष गुजराती धर्मशाला समिति देवास, तेजकुमार चौहान ,पीरूलाल छड़ावदिया, प्रकाश चन्द्र चौहान, तेजुराम चांदना, शंकर लाल मालवीय, ओंकार सिंह मालवीय, बाबूलाल धानक, शिवजीराम गरोड़ा, मोहनलाल गरोड़ा, राजकुमार परमार, राजेश कुमार मालवीय, रवि तोमर, राजेन्द्र कुमार सुमन, मांगीलाल गुजराती, संजय परमार, विष्णु प्रसाद कलथिया, अभिषेक परमार, शिवनारायण मालवीय, रमेश चंद्र चौहान, सुरेश चंद्र सोलंकी, जगदीश पंवार, मेहरबान सिंह चौहान, तेजुलाल मालवीय, भगवान सिंह धानक, बाबूलाल मालवीय, राहुल मालवीय, विरेन्द्र धानक, रोहित सागर पंवार,सुमित भांडवा आदि। कार्यक्रम का संचालन दयाराम मालवीय (अजाक्स साहित्य प्रकोष्ठ अध्यक्ष देवास) द्वारा किया गया एवं छगनलाल सोलंकी अजाक्स तहसील देवास अध्यक्ष ने आभार व्यक्त किया।

पटेल परिवार ने 35 वर्ष बाद मनाई शरद पूर्णिमा

देवास। ग्राम छायन के पटेल परिवार में 35 वर्षों बाद शरद पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पटेल परिवार में 35 वर्ष पूर्व शरद पूर्णिमा के दिन परिवार की एक महिला का देहांत हो गया था। इस कारण से मान्यताओं के अनुसार ओटन होने से शरद पूर्णिमा नहीं मनाई गई लेकिन इस वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन ही परिवार के अरूणसिंह परिहार के यहां पुत्र का जन्म हुआ ओर वह ओटन खुल गई और पटेल परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। पटेल परिवार ने हर्षोल्लास के साथ शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया।

एक शाम किशोर के गीतों के नाम आज

देवास। यंग मेलोडियंस ऑर्केस्ट्रा ग्रुप देवास के तत्वाधान मे आज 19 अक्टूबर शनिवार को शाम 6 बजे से मल्हार स्मृति मंदिर में एक शाम किशोर कुमार के गीतों के नाम (आ चल के तुझे में लेके चलूं) का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसन्न कुमार जूनियर किशोर कुमार जबलपुर, किशोर कुमार के गीतों की सुमधुर प्रस्तुति देंगे। मुश्ताक शाह वारसी ने सभी संगीत प्रेमियों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारकर कार्यक्रम का आनंद लें।

शरदोत्सव समिति ने पूर्व फौजियों, रक्तदाताओं, मेघावी छात्राओं को किया सम्मानित, उत्कृष्ट सांस्कृतिक सम्पन्न

हीरालाल गोलानी सोहागपुर। शरद पूर्णिमा के अवसर पर शारदोत्सव समिति के लगातार चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की 24 वर्ष की बैला पर पूर्व फौजियों, रक्तदाताओं के अलावा मेधावी छात्राओं का प्रतिवर्षानुसार सम्मानित किया गया। कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक ठाकुर विजयपालसिंह,नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष लता यशवंत पटेल, विख्यात बुन्देली कवि राजेन्द्र सहारिया, आधावाहिक सुहागन की नगर को गौरवान्वित करने वाली कलाकार गरिमा किशनानी एसडीओ पुलिस संजू चौहान ,नगर निरीक्षक कंचनसिंह आदि आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अतिथियों ने पूर्व फौजियों नायक नीलम पटैल, हवलदार नरेन्द्र शर्मा, हवलदार संतोष रघुवंशी,हवलदार देवेन्द्र मालवीय,नायक लहरी कुशवाहा ,हवलदार विजय दुबे, हवलदार जितेन्द्र ठाकुर, नायक लीलाधर रघुवंशी,हवलदार बालमुकुद गुर्जर, नायक दिनेश ठाकुर, हवलदार मालकजी पटैल, नायक बालकिशन विश्वकर्मा, अजय सोनी, एएसआई सुरेश कसेरा, हवलदार राजेश रघुवंशी, हवलदार मनोहर सांगा, सिपाही सचिन मिश्रा, हवालदार साहूकार,हवलदार

रामप्रकाश रघुवंशी नेपाल रघुवंशी , रक्तदाताओं मानस पुरोहित,छविलाल अहिरवार दीपक कुशवाहा , सौरभ अहिरवार, राहुल चौधरी, हर्ष कोरी राजकुमार ठाकुर, कृष्णा मैहर , लक्की किशनानी श्यामत , जलील शाह, मुकेश पटेल, शरद शिवप्रसाद चौरसिया, शफीक, शुभम चौरसिया दुविताल चौरसिया, हेप्पी नामदेव, जितेन्द्र कुमार ,मेधावी छात्र सम्मान प्रियांशी कसेरा, मंयक रघुवंशी , नीलेश अहिरवार ,उभरते कलाकार, सुहागन धारावाहिक कलाकार गरिमा किशनानी, शिव प्रजापति, गोलू प्रजापति, पिंकी भावसार, राहुल कुशवाहा, प्रशासनिक सम्मान एसडीओ पुलिस संजू चौहान, नगर निरीक्षक कंचनसिंह , नगरपालिका अधिकारी राकेश मिश्रा, नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष लता यशवंत पटैल आदि को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की बैला रात 2बजे तक चलती रही। कार्यक्रम का संचालन आयोजक पवनसिंह चौहान ने किया। आभार शरदोत्सव समिति अध्यक्ष प्रदीप देवलिया ने व्यक्त किया। इसके पूर्व मां सरस्वती, भारत माता एवं संत बाल्मीकि जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व फौजियों के सम्मान के अवसर पर देश भक्ति गीतों की धुन पर भूतपूर्व सैनिकों को सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया। और जिनका प्रमाण पत्र देकर माला पहनकर उनका सम्मान किया गया। आयोजक पवनसिंह चौहान एवं अध्यक्ष प्रदीप देवलिया ने समिति सदस्यों का सहयोग करने पर आभार व्यक्त किया है। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक के अलावा भारी जनसमुदाय उपस्थित था।

बच्चे मिल रही सुविधाओं का लाभ लेकर मन लगाकर पढ़ें और बेहतर समाज के निर्माण में भागीदार बनें : कलेक्टर

देवास । स्कूलों को उद्योगों और समाजसेवियों की मदद से मिल रहे फर्नीचर, टीवी और अन्य संसाधनों की मदद से मिल रही सुविधाओं का लाभ लेकर अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिये ताकि आने वाले कल में वे अच्छे नागरिक बन कर बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी कर सकें । ये बात जिलाधीश ऋषव गुप्ता ने कही। वे चिमनाबाई स्कूल में बेअरलॉकर उद्योग द्वारा स्कूलों में दिए जाने रहे फर्नीचर के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे।आपने जिले के विकास कार्यों में बेअरलॉकर उद्योग के सहयोग के लिये उद्योग प्रबंधन की प्रशंसा भी की। जिलाधीश के निर्देशानुसार उद्योगों द्वारा स्कूलों को अपने सीएसआर फण्ड से दी जाने वालीं सहायता के तहत बेअरलॉकर उद्योग द्वारा चिमनाबाई स्कूल में डेढ़ लाख कीमत के पचास फर्नीचर सेट भेंट किए गए। उद्योग के प्रबंधक प्रवीण शर्मा तथा सीएसआर सहयोगी एक्ट ईव फाउंडेशन अध्यक्ष मोहन वर्मा ने बताया कि फर्नीचर लोकार्पण के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऋषव गुप्ता के साथ बेअरलॉकर उद्योग के जर्मनी से आए जुजर्न बेयर, टर्की से आए डाडस माहिर,इन्डिया ऑपरेशन हेड हितेश कंवर, संदीप गगलानी, जिला शिक्षाधिकारी हरिसिंह भारती, डीपीसी प्रदीप जैन,उद्योग विभाग महाप्रबंधक मंगल रैकवार,डाइट प्राचार्य आर के सक्सेना, बीआरसी किशोर वर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। बेअरलॉकर उद्योग के जर्मनी से आए जुजर्न बेयर ने कहा अपनी सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी के तहत हमारे द्वारा समाज के लिए जो बेहतर है वो करते हुए हमें खुशी हैं। इन्डिया ऑपरेशन हेड हितेश कंवर ने कहा हम अब तक बच्चों के लिए 400 फर्नीचर सेट दे चुके हैं और एक हजार सेट और भी देने जा रहे हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल,माता टेकरी और दृष्टिहीन कन्या शाला मे मांग पर सोलर सिस्टम भी लगाये हैं। कार्यक्रम के आरंभ में स्कूल प्रबंधन की तरफ से प्रभारी प्राचार्या सीमा पांडे ने तथा एक्टईव फाउंडेशन अध्यक्ष मोहन वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सिद्धि कुकडे,प्रदीप शर्मा, योगेन्द्र सिंह चावडा,ईसाक शेख,शैलेन्द्र जोशी, मुकेश तिवारी, वंदना शर्मा,विजय श्रीवास्तव, गुलाब वर्मा,आर के श्रीवास्तव, जनशिक्षक सुरेंद्र राठौर,सहित स्कूल स्टाफ उपस्थित था। कार्यक्रम का संचालन किशोर असनानी ने किया तथा आभार दीपक शुक्ला ने माना।

मीना बाजार में कवि सम्मेलन हुआ सम्पन्न

देवास । नगर पालिक निगम द्वारा आयोजित 88 वीं दशहरा कृषिकला एवं औद्योगिक प्रदर्शनी 2024 मीनाबजार के अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन रात्रि 2.30 बजे तक चला। कवि सम्मेलन में विभिन्न कविताओं की सरस रस वर्षा हुई। मंच संचालक सबरस कवि शशिकांत यादव शशि द्वारा मंचीय सुचिता से परिपूर्ण, सारगर्भित, गरिमामय संचालन में दिल्ली से पधारी सुनामधन्य कवियित्री डॉ. कीर्ति काले द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ । निरंतर बढ़ती हुई रात्रि के साथ कविताओं की सरस रसवर्षा के समापन- समारोह पर कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे शहर के वरिष्ठ राष्ट्रवादी कवि देवकृष्ण व्यास ने अपनी बुलंद शैली एवं आवाज में भगवा को तिरंगे का पूर्वज निरूपित करते हुए रंगो के आधार पर भगवा के शौर्य, पराक्रम, सनातन सत्य को गाया तो बड़ी संख्या में उपस्थित काव्यरसिक खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट करते नजर आए । सूत्रधार शशिकांत शशि ने पूर्ण विश्वास के साथ प्रथम कवि के रूप में लखनऊ से आए ओजस्वी कवि अभय निर्भीक को कवितापाठ के लिए आमंत्रित किया, अभय ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रचनाओं के साथ देश के ज्वलंत एवं संवेदनशील विषय शहीद के परिवार की भावनाओं को कविता के माध्यम से सुनाते हुए श्रोताओं की आंखें नम हो गई, तब श्रोताओ की करतल ध्वनि के साथ कवि सम्मेलन प्रारंभ से ही ऊंचाई को छू गया। मुम्बई से आए लाफ्टर हास्य, व्यंग्य के प्रसिद्ध कवि सुनील व्यास ने चुटीली रचनाओं से श्रोताओ को खूब गुदगुदाया ।

जिंदगी आड़े, तिरछे मोड़ है- देवास के प्रखर, ओजस्वी गीतकार जगदीश सेन ने अपनी विधा से हटकर, जिंदगी आड़े- तिरछे मोड़ है, मोड़ में भंवरे जैसे जोड़ है, उस पथ पर चलते हुए, बचकर निकलते हुए जीना है जिंदगी...इस सरस गीत की प्रस्तुति दी, तब लगा कि मां वीणावादिनी के साधकों के मंचो पर दीर्घकालिक, प्रेरणादायी गीत आज भी अपनी पूर्ण पहचान लिए स्थापित है । इसके बाद तो वाराणसी से आमंत्रित हास्य, व्यंग्य के कवि अनिल चौबे ने फूहड़ चुटकुलों से परे रस, छंद, अलंकार सहित हास्य प्रस्तुति दी । कवियत्री डॉ. कीर्ति काले जी ने संदेशप्रद मुक्तक, गीत, गजल से मन मोहा ।

दूरसंचार महाप्रबंधक ने किया भजन गायक द्वारका मंत्री का अभिनंदन

मां चामुंडा सेवा समिति भंडारा अमरनाथ के भंडारे की याद ताजा कर रहा है.. भजन गायक द्वारका मंत्री

देवास। मां चामुंडा की नगरी देवास में मालवांचल के प्रसिद्ध भजन गायक द्वारका मंत्री का मां चामुंडा सेवा समिति के संरक्षक महाप्रबंधक दूरसंचार विभाग पंकज उपाध्याय द्वारा शाल श्रीफल, मां की चुन्री व पगड़ी पहनकर पुष्पमालाओं से आत्मीय अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि बैंक नोट प्रेस के मुख्य महाप्रबंधक केदारनाथ महापात्रा, अभिराज सिंह ठाकुर, डीएफओ प्रदीप मिश्रा थे। डॉ लीलाधर घनघोरिया, डॉक्टर अरुण दुबे, डॉक्टर कृष्णकांत धुत, डॉक्टर सलूजा विशेष अतिथि थे। भजन गायक द्वारका मंत्री ने इस दौरान मां मुरादे पूरी कर दो हलवा बांटूंगा की सुमधुर प्रस्तुति से श्रद्धालु झूम उठे। द्वारका मंत्री ने कहा कि मां चामुंडा टेकरी पर मां के दर्शनार्थ आने वाले लाखो श्रद्धालुओं के लिए मां चामुंडा सेवा समिति द्वारा अनवीरत 24 घंटे लगाया गया विशाल महाप्रसादी भंडारा अमरनाथ में 24 घंटे चलने वाले भंडारे की याद ताजा कर रहा है। अमरनाथ के भंडारे की तरह मां चामुंडा सेवा समिति का 24 घंटे चलने वाला भंडारा देवासवासियो के लिए अविस्मरणीय है। दानदाताओं के अनुकरणीय सहयोग से 9 दिनों तक लाखों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का विशाल भंडारा चलता है। इस अवसर पर मां चामुंडा सेवा समिति के समाजसेवी नरेंद्र मिश्रा, रामेश्वर जलोदिया, कैलाश शर्मा, नारायण व्यास, उम्मेद सिंह राठौड़, इंदर सिंह गौड़, दिनेश सांवलिया, मात्र शक्तियां मंजू जलोदिया, सुधा सोलंकी, प्रेमलता चौहान, कला तंवर, संगीता जोशी सहित समाजसेवी एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।

जीवन का उद्देश्य जानना हो तो इसका महत्व जानें : साध्वी शारदाजी

ग्राम खरड़ीपुरा में आयोजित सत्संग समारोह में सतपाल जी महाराज की शिष्या ने दिया आध्यात्मिक संदेश

देवास। धर्म और आध्यात्म की दुनिया में यह सवाल बहुत पूछा जाता है कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है ? अब इसका उत्तर जानने के लिए पहले यह समझा जाए कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है। यदि महत्व समझ में आ जाए तो उद्देश्य जानना आसान हो जाएगा। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा महत्व है कि आप अपनी आत्मा तक जा सकते हैं। अन्य जीवों के पास यह अवसर नहीं होते। सबसे पहले यह भी समझना होगा कि हम आत्मा है और इस समय शरीर में है और जब हम खुद को पहचानने का प्रयास करेंगे तो आत्मा की ओर चलना ही पड़ेगा। शरीर तो एक बाहरी आवरण है।

यह बात ग्राम खरड़ीपुरा में समाज सेवी अध्यात्म प्रेमी मानव उत्थान सेवा समिति के सक्रिय सदस्य स्व.गोविंद सिंह नायक की स्मृति में आयोजित रात्रि कालीन सत्संग समारोह में सतपाल महाराज की शिष्या शारदाबाई जी ने कही। उन्होंने कहा इस शरीर के भीतर जो मन है, वही आत्मा तक जाने से रोकता है। तो शरीर को अयोध्या की तरह सद्गुणों से सजाएं, रामलला की स्थापना अपने भीतर करें और फिर चलें आत्मा की ओर। तब समझ आएगा कि मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। आसपास क्षेत्र से बड़ी संख्या में उपस्थित अध्यात्म प्रेमियों को समझाते हुए संत श्री ने कहा जीवन की

सफलता का रहस्य आत्म-जागृति में निहित है। जिस प्रकार सोया हुआ व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ रहता है, उसी प्रकार आत्मा के जागरण से विमुख व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों से अपरिचित रहता है। भ्रमित मनुष्य अक्सर शक्ति को केवल शारीरिक क्षमता के रूप में देखता है, जबकि शारीरिक शक्ति तो बाहरी प्रदूषण मात्र है। वास्तविक शक्ति हमारे भीतर है और इस आंतरिक शक्ति की क्षमता अपार होती है। इसके अनुभव के लिए आत्म जागृति आवश्यक है। आंतरिक शक्ति को जागृत करने का पहला कदम है स्वयं के भीतर की यात्रा करना, आत्म चिंतन करना और अपनी चेतना के गहन स्तरों तक पहुंचना। आत्मा के साक्षात्कार के बिना हम अपने वास्तविक स्वरूप और अपनी अनंत क्षमताओं से वंचित रहते हैं।

इस मौके पर उपस्थित सेविका सरिता बहन ने ज्ञान-भक्ति, वैराग्य, गुरु महिमा से ओतप्रोत मधुर भजन प्रस्तुत करते हुए कहा जीवन में सफलता तो प्रत्येक मनुष्य की अभिलाषा होती है, लेकिन सभी उसके लिए पर्याप्त परिश्रम एवं पुरुषार्थ नहीं कर पाते। परिश्रम एवं पुरुषार्थ की राह में आलस्य एक बड़ा अवरोध है। आसपास क्षेत्र से आए निर्गुणी भजन गायक कलाकारों ने देर रात्रि तक भजन प्रस्तुत किये।

संयुक्त मोर्चा ने निगम आयुक्त को दिया 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन

25 अक्टूबर तक वेतन नहीं मिलने पर करेंगे हड़ताल

देवास। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन रजि 7262, राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा एवं म.प्र. सफाई कर्मचारी महासंघ ने निगम आयुक्त रजनीश कसेरा को सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि नगर पालिक निगम देवास में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त समस्त कर्मचारी वर्ष 2007 से वर्ष 2016 तक विनियमित देवेभो, 29 दिवस को नियमित स्थायीकरण का लाभ दिया जाए, क्योंकि जन अभियान परिषद विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग में वर्ष 2007 से 2016 के बीच देवेभो को विनियमित किया जा चुका है। पूर्व में बंद हुए सफाई कर्मचारियों को पुनः कार्य पर रखा जाये। 45 वार्ड में प्र. दरोगाओं को थम्ब मशीन प्रदान की जाये, प्रतिदिन मोबाईल हैंग व अन्य समस्याओं के कारण कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज हो जाती है। देवेभो विनियमितिकरण कर्मचारी की मृत्यु उपरांत उसके परिवार के सदस्य को मानवीय आधार पर नौकरी पर रखा जावे, जिससे उसके परिवार का पालन, पोषण हो सके।

पूर्व में परिषद द्वारा समस्त संवर्ग के 810 कर्मचारियों को विनियमितिकरण किये जाने का संकल्प भी हो चुका है जिसके उपरांत भी आज दिनांक तक विनियमित नहीं किया जा सका है, जो कि कर्मचारियों के हितों का खुला शोषण एवं अधिकारों से वंचित रखा जाना है। वर्तमान में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों को रखे जाने से स्थापना व्यय बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भविष्य में कर्मचारियों को नियमित, विनियमित किये जाने में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शासन के आदेश के क्रम में दीपावली पूर्व समस्त कर्मचारियों का 25 अक्टूबर को वेतन आहरित किया जावे। सात दिवस के अंदर उक्त मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो संगठन द्वारा हड़ताल की जाएगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव राजू सांगते, प्रदेश कार्यवाह अध्यक्ष रूपेश कल्याणे, प्रदेश सचिव विजय सांगते, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल पहलवान खरे, राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा के संरक्षक लालचंद डागर, जिलाध्यक्ष पारस कलोसिया, शहर अध्यक्ष राकेश बंजारे, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के शहर अध्यक्ष राजेश गौसर एवं म.प्र. सफाई कर्मचारी महासंघ के शहर अध्यक्ष संजय सांगते काका, , विनोद भरोसिया, दीपक खरे, संजय सांगते, प्रवीण खरे, शैलेन्द्र मकवाना, उमेश सांगते, बसंत कल्याणे, बसंत कल्याणे, लोकराज गिल्होरे, रजनीश वेद, जगदीश घावरी, कैलाश सोलंकी, ललित सोनवाने, विजय आदिवाल, अनूप सांगते, राकेश गौसर, विनय सांगते विनू, विरेन्द्र शिंदे, रईस खान, मुकेश बंजारे, संजय मेवाती, रवि खरे, मंगल घारू, श्याम घारू, मनीष बंजारे, विजय गोयल, सावन धोलपुरे, जितेन्द्र डुमाने, आनंद बंजारे, सोनू डुमाने, सुनील फतरोड़, जितेन्द्र डागर, अमर धनराज सांगते, राजकुमार कल्याणे, ऋषि निगम, रईस खान, कैलाश सोलंकी, दीपक सांगते, महेश लोट व दरोगा साथी उपस्थित रहे।

राइट क्लिक

'न्याय की देवी' की सूरत बदली पर न्याय प्रणाली की सीरत भी बदलेगी?

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के वरिष्ठ संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

आजादी के 75वें साल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'न्याय की देवी' की आंखों से पट्टी हटाने का फैसला न्याय के प्रति नैतिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक भले हो, लेकिन इससे देश में बेहद धीमी गति से काम कर रही न्याय व्यवस्था में सुधार और लोगों को त्वरित और स्वीकार्य कैसे मिलेगा, इसका कोई जवाब नहीं मिलता। 'न्याय की देवी' के स्वरूप और तेवर का भारतीयकरण हो, यह अच्छा है, लेकिन न्याय प्रणाली अपने काम काज में भी 'देसी ढर्रे' पर ही चले, यह गंभीर चिंता का विषय है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रतीकात्मक बदलाव इस मायने में अच्छा है कि हम न्याय प्रणाली का भी स्वदेशीकरण करना चाह रहे हैं, भले ही हमें यह औपनिवेशिक व्यवस्था अंग्रेजों से विरासत में मिली हो। इस लिहाज सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी यूरोपीय शैली में 'न्याय की देवी' की वही प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसकी मूल अवधारणा रोमन सभ्यता की रही है। अर्थात् एक रौबदार देवी के दाएं हाथ में न्याय की तराजू और बाएं हाथ में तलवार। देवी की आंखों पर पट्टी का अर्थ यह कि वह बिना पक्षपात के न्याय देगी। तराजू के मायने यह कि सभी पक्षों को समान रूप से सुना जाएगा और तलवार न्याय के पारदर्शी होने और कानून के पालन की गारंटी है। रोमन अवधारणा में यह देवी 'जस्टिशिया' है। हालांकि इस न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी के कई अर्थ हैं, जिसमें से एक निष्पक्ष न्याय की जगह कानून के अंधा होने से भी है। कानून के मानवीय और सामाजिक सरोकारों से परे होने से है। यही कारण है कि ग्रीक और रोमन संस्कृति के वारिस आज यूरोप के कुछ देशों में 'न्याय की देवी' की आंखों पर से पट्टी हटा दी गई है। मसलन कनाडा में तो न्याय की देवी सिर से पैर तक केवल एक लबादा ओढ़े दिखती है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन हाथों में न तो तराजू है और न ही तलवार। खुद रोम में न्याय की देवी के दाएं हाथ में तलवार की जगह पुस्तक दिखाई गई है। हो सकता है कि न्याय की नई भारतीय देवी के हाथों में तलवार की जगह संविधान देने का विचार इसी से आया हो।

वैसे भारतीय परंपरा में 'न्याय की देवी' जैसी कोई संकल्पना नहीं है। सनातन धर्म में शनि को ही न्याय का देवता कहा गया है। लेकिन शनि भय और अनिष्ट का प्रतीक ज्यादा हैं। इसका कारण शायद है कि भारतीय दर्शन में न्याय शास्त्र की विशद व्याख्या तो है, लेकिन ऐहिक जीवन में किए गए अपराधों की संहिताबद्ध विधि प्रणाली के जरिए सुनवाई कर दंड देने जैसी सुस्पष्ट व्यवस्था नहीं है। हम जीवन को समग्र रूप देखते हैं और जीवन भर के पाप और पुण्य कर्मों का फल अगले जन्म में भोगने अथवा इन सबसे मुक्ति के बतौर मोक्ष पाने में विश्वास करते हैं। यह फल धर्म और अधर्म के हिसाब से किए गए कार्यों के मुताबिक पुनर्जन्म में श्रेष्ठ अथवा निम्न योनि में जन्म के रूप में होता है। ऐसे में शायद भारतीयों को किसी 'न्याय की देवी' की अलग से कल्पना की जरूरत ही न पड़ी हो। दूसरे, ज्यादातर विवाद पंचायत अथवा सामाजिक स्तर पर ही निपट जाते थे, इसलिए अलग से अदालत जैसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे, राजा ही सर्वोच्च अदालत था और उसका धर्माचरण ही न्याय की गारंटी था।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट में स्थापित नई प्रतिमा की स्थापना के पीछे परिकल्पना प्रधान न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड की है। वो चाहते थे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 'न्याय की देवी' की छवि भी भारतीय हो। यह बात मूर्तिकार विनोद गोस्वामी की कृति में भी दिखाई देती है। नई प्रतिमा में देवी का चेहरा भारतीय है। वह जस्टिशिया की तरह आक्रामक और रौबदार न होकर सौम्य है। नई देवी रोमन स्त्रियों की तरह ट्यूनिक की बजाए साड़ी पहने हुए है। उसकी आंखें स्पष्ट रूप से दुनिया देख रही हैं और दाएं हाथ में तलवार की जगह देश का राष्ट्रीय ग्रंथ 'संविधान' है। इसके पीछे यह संदेश देने की कोशिश भी है कि 'न्याय की देवी' की प्रतिबद्धता संविधान की भावना के अनुसार सभी को निष्पक्ष न्याय देने की है।

जज्बाती तौर पर 'न्याय की देवी' के भाव बदलने की यह कोशिश अच्छी है, लेकिन व्यवहार में इस देश में निष्पक्ष और त्वरित न्याय मिलने और कानून के प्रभावी अनुपालन की कहानी बहुत आश्वस्त करने वाली नहीं है। इसका पहला कारण तो देश भर की अदालतों में न्यायाधीशों की कमी और न्याय प्रणाली का कछुए की चाल से काम करना है। अगर अदालतों में पर्याप्त संख्या में जज ही नहीं होंगे तो फैसले जल्द कैसे होंगे? भारत सरकार ने लोकसभा में 23 जुलाई 2023 को एक सवाल के जवाब में बताया था कि देश भर में निचली अदालतों में 5388 जजों के पद खाली पड़े हैं। देश की निचली अदालतों में जजो के स्वीकृत पद 25 हजार 246 हैं, लेकिन काम 19 हजार 858 ही कर रहे हैं। इन पदों पर नियुक्तियां राज्य सरकारों को ही करनी होती हैं, लेकिन वहां भी हद दर्जे की लेतलाली है। राजनीतिक गुणा भाग हैं। जोड़-तोड़ है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में जजों के रिक्त पदों पर लगभग पूरी नियुक्तियां हो गई हैं, लेकिन हाई कोर्टों में 327 जजों के पद अभी भी खाली हैं।

एक तरफ जजों की कमी, दूसरी तरफ अदालतों में मुकदमों का बढ़ता अंबार। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वर्तमान में देश की निचली अदालतों में कुल 5.1 करोड़ मामले लंबित हैं। अकेले सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग मामलों की संख्या 82 हजार है जबकि हाई कोर्टों में 58.62 लाख मामले फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। इनमें भी 42.64 लाख मामले तो दीवानी हैं। नई भारतीय न्याय संहिता में फौजदारी मामलों में तो फिर भी विवेचना की कोई समय सीमा तय की गई है, लेकिन दीवानी मामलों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। देश की अदालतों में 1 लाख 80 हजार मामले तो ऐसे हैं, जो 30 साल से चल रहे हैं। इनका फैसला कब होगा, कोई नहीं जानता। ऐसे में पीढ़ियों तक मुकदमे चलते रहते हैं। नीति आयोग ने 2018 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अदालतों में इसी तरह धीमी गति से मामले निपटते रहे तो सभी लंबित मुकदमों के निपटारे में 324 साल लगेंगे। यह स्थिति तब है कि जब 6 साल पहले अदालतों में लंबित मामले आज की तुलना में कम थे।

न्याय के निष्पक्ष होने के साथ यह भी आवश्यक है कि वह समय रहते मिले। अन्यथा उस न्याय का, चाहे वह कितना भी निष्पक्ष क्यों न हो, का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। आपराधिक और दीवानी विवादों के जितने मुकदमे अदालतों में पहुंच रहे हैं, उस तुलना में उनकी सुनवाई करने और फैसला देने वालों जजों की संख्या बहुत कम है। आज भारत में हर 10 लाख की आबादी पर औसतन 21 जज काम कर रहे हैं। जबकि यूरोप में यही औसत प्रति दस लाख 210 और अमेरिका में 150 जजों का है। अगर हम अमेरिका के मानदंड को भी मानें तो भारत की 145 करोड़ की आबादी पर लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए कुल 2 लाख 17 हजार जज चाहिए जबकि हैं 20 हजार भी नहीं। जजों की नियुक्तियों का काम सरकार का है, लेकिन ज्यादातर सरकारें इस मामले में गंभीर नहीं दिखतीं। परोक्ष रूप से यह रवैया जनता को न्याय के अधिकार के वंचित करने जैसा ही है। इसके अलावा भारतीय अदालतों में बुनियादी और अधोसरंचनात्मक सुविधाओं की कमी की तो अलग ही कहानी है। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर सर्वोच्च अदालत में 'न्याय की देवी' की सूरत बदली है तो आगे न्याय प्रणाली की सीरत भी बदलेगी। लेकिन कैसे यह सवाल अभी बाकी है।

सड़कों की क्वालिटी पर आज से मंथन, गडकरी होंगे शामिल

मंत्री राकेश सिंह ने कहा- एक्सपर्ट एक मंच पर अनुभव और सुझाव साझा करेंगे

भोपाल (नप्र)। सड़क और पुल निर्माण की क्वालिटी में सुधार लाने और नई तकनीक से टाइम लिमिट में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने को लेकर शनिवार और रविवार को मंथन होगा। भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित सेमिनार का आयोजन भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) और एमपी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) करेगा। इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे।

एमपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। कहा- सेमिनार में सरकारी और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर अनुभवों और नवाचारों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि प्रदेश की अधोसंरचना परियोजनाओं को और मजबूती मिल सके। सेमिनार में सड़क और पुल निर्माण की नई तकनीक, सामग्रियों के उपयोग और एग्रीमेंट से जुड़े पहलुओं पर एक्सपर्ट्स अपने अनुभव और सुझाव साझा करेंगे।

दो दिन इन विषयों पर होगा मंथन- शनिवार, पहला दिनः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नई तकनीकों पर अमल, पुल निर्माण में नई मशीनरी का उपयोग और सड़क निर्माण में उपयोग होने वाली नई सामग्रियों पर फोकस रहेगा। सड़क सुरक्षा, परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए आईटी तकनीकों का उपयोग और सीमांत सामग्रियों के उपयोग पर भी गहन मंथन किया जाएगा।

रविवार, दूसरा दिनः 20 अक्टूबर को ईपीसी ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन) एग्रीमेंट्स की तैयारी व शेड्यूलिंग, एग्रीमेंट करने में ठेकेदारों और सहायक अभियंताओं की भूमिका पर विस्तृत चर्चा होगी। इसमें अनुबंधों से जुड़े विवादों और चुनौतियों के समाधान पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह बोले

लोक निर्माण से लोक कल्याण हमारी टैगलाइन है। जिसका उद्देश्य केवल संरचनाओं का निर्माण करना भर नहीं है बल्कि ऐसी परियोजनाओं का विकास करना है जो समाज के सतत विकास में अपना योगदान दें। इसलिए हमारा लक्ष्य भविष्य की सभी परियोजनाएं, इफेक्टिव मैनेजमेंट, कम लागत और समयबद्ध कार्य की दृष्टि से आदर्श बने। मंत्री राकेश सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो दिनी सेमिनार की डिटेल्स दी।

उद्घाटन सत्र में इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन प्रक्रिया पर चर्चा

सेमिनार के पहले दिन 19 अक्टूबर को उद्घाटन-सत्र में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह मौजूद रहेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी-सत्र आयोजित किए जाएंगे जिनमें देशभर से आए हुए विशेषज्ञ नई तकनीकों, निर्माण सामग्रियों और ईपीसी (ईपीसी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन) एग्रीमेंट प्रक्रिया की चुनौतियों पर अपने विचार साझा करेंगे।

प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है : कृषि मंत्री श्री कंषाना

भोपाल (नप्र)। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है किप्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार ने खरीफ में किसानों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया है और रबी में भी इसी प्रकार से किसानों की आवश्यकतानुसार उर्वरक उपलब्ध करायेगें। मंत्री श्री कंषाना श्यामला हिल्स स्थित निवास पर मीडिया से चर्चा में यह बातें कही।

मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि फसलों के लिये नाईट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। डीएपी से नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की ही पूर्ति हो पाती है, जबकि एनपीके के उपयोग से नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश तीनों तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इसलिये किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा डीएपी के स्थान पर एनपीके के उपयोग की सलाह दी जा रही है।

केन्द्र सरकार ने डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ा दी है जिससे कि किसानों को किसी तरह की समस्या न हो। एक बैग यूरिया की कीमत 2 हजार 265 रूपये है। जबकि सरकार इसे सस्ते दर पर किसानों को 266.50 रूपये में उपलब्ध करा रही है। इसी प्रकार डीएपी की एक बैग की कीमत 2 हजार 446 रूपये है, जबकि सरकार इसे किसानों को 1 हजार 350 रूपये प्रति बैग उपलब्ध कराती है। मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि प्रदेश में किसानों को खरीफ के मौसम में दी जाने वाली सब्सिडी की गणना करें तो यह यूरिया के लिए 7 हजार 32 करोड़ रूपये एवं डीएपी के लिये 1 हजार 258 करोड़ रूपये होगी। यह सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डीएपी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव का कारण यूक्रेन और इजराइल संघर्ष है। इनके संघर्ष के कारण आपूर्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ा है। फिर भी किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है।

मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि खरीफ 2024 में किसानों को 32.97 लाख मीट्रिक टन की मांग के विरूद्ध 33.69 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराया गया है, जबकि पिछले वर्ष खरीफ 2023 में 32.62 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध कराया गया था। इसी प्रकार रबी 2024 में 41.10 लाख मीट्रिक टन की मांग के विरूद्ध 01 अक्टूबर 2024 से अभी तक 19 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराया गया है। जिसमें 7.74 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.21 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 6.05 लाख मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध करा दिया गया है।

मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि प्रदेश में रबी 2024 के लिए भी पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो उर्वरकों का अग्रिम भंडारण करता है ताकि किसानों को उर्वरक की कोई कमी न हो। रबी सीजन की शुरुआत में राज्य ने पहले ही 6.55 लाख मीट्रिक टन अग्रिम भंडारण कर लिया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने का आश्वासन मिला है और लगातार उर्वरक प्राप्त भी हो रहे है। किसानों को उनकी मांग के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जायेगा।

मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि 'नैनो यूरिया' और 'नैनो डीएपी' भी किसानों को उपयोग करने की सलाह दी गई है। फूल आने से पहले स्प्रे करने से उपज में वृद्धि होती है। किसानों को उर्वरको की बिक्री पर अन्य उर्वरक टैग करने के लिये कोई दबाव नही डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिए गए उर्वरक गुणवत्तापूर्ण हों। जहाँ भी घटिया गुणवत्ता के उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक ब्रिकी की सूचना मिलेगी, उनके विरूद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कालाबाजारी और नकली उर्वरकों के मामले में हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दी एमपी को सौगात

भोपाल - कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर फोरलेन में होगा अपग्रेड; 3589 करोड़ मंजूर

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश में भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4-लेन में अपग्रेड करने का ऐलान किया है। इसके लिए भोपाल से विदिशा, विदिशा से ग्यारसपुर, सताईघाट से चौका और चौका से कैमाहा पैकेजों के लिए 3589.4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। मंडला-नैनपुर मार्ग के लिए भी 592 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

सीएम ने पीएम मोदी व केंद्रीय मंत्री का माना आभार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश को विकास पथ की सौगात देने पर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गडकरी का आभार माना है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सरकार बढ़ती रोड कनेक्टिविटी के जरिए विकास का नया अध्याय लिख रही है। भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 4-लेन में अपग्रेडेशन से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यातायात सुगमता के साथ ही सड़क दुर्घटना में भी कमी आएगी। व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

संकल्प पत्र में की थी घोषणा

मध्यप्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र के तहत बुंदेलखंड विकास पथ की घोषणा की थी। यह राज्य की राजधानी भोपाल को बुंदेलखंड के सागर और छतरपुर जिलों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण 4-लेन सड़क परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य भोपाल से सागर होते हुए छतरपुर और उत्तरप्रदेश बॉर्डर तक की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा इस मार्ग को 4-लेन में अपग्रेड करने की प्रोसेस पहले से जारी थी, लेकिन कुछ हिस्सों के लिए मंजूरी लंबित थी। आज नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भोपाल से सागर और छतरपुर से उत्तरप्रदेश बॉर्डर तक इस मार्ग को 4-लेन में अपग्रेड करने की अनुमति दी गई है।

इस परियोजना की कुल लागत 3589.4 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। इस स्वीकृति से बुंदेलखंड विकास पथ के निर्माण में तेजी आएगी और सरकार के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाएगी। इसी के साथ मंडला से नैनपुर तक 46 किलोमीटर लंबे मार्ग को अपग्रेड करने के लिए भी 592 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस मार्ग के अपग्रेड होने से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित और कुशल बनाया जाएगा।

रेप के आरोपी ने मां-बेटी को चाकू मारे, सुसाइड किया

मां-बेटी की हालत गंभीर; समझौता करने का दबाव बना रहा था

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर में रेप केस के एक आरोपी ने 20 वर्षीय युवती और उसकी मां पर चाकू से हमला करने के बाद खुद को चाकू मारकर आत्महत्या कर ली। घटना रांझी थाना के रिछाई के पास की है। मां-बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार गुरुवार रात करीब 10 बजे 26 वर्षीय युवक विशाल उर्फ शुभम राजपूत युवती के घर पहुंचा और विवाद करने लगा। कुछ ही देर बाद स्थिति ऐसी बनी कि आरोपी ने युवती और उसकी मां पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर गंभीर रूप से घायल कर खुद को बाथरूम में बंद किया और फिर चाकू मार लिया।

विवाद की जानकारी पड़ोसियों ने रांझी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर विशाल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात में घायल युवती और उसकी मां की हालत भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था- अमखेरा निवासी विशाल राजपूत के खिलाफ 2023 में गोहलपुर थाने में युवती ने रेप का केस दर्ज करवाया था। उस दौरान युवती अपनी मां के साथ आरोपी के घर के पास रहा करती थी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने

विशाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विशाल करीब छह माह पहले जेल से छूटकर आया। कुछ दिनों से युवती और उसकी मां पर समझौता कर केस वापस लेने का दबाव बनाने लगा। इस बीच विशाल की युवती से झड़प भी हुई।

जून 2024 में युवती ने फिर से विशाल के खिलाफ गोहलपुर थाने जाकर धमकाने और केस वापस लेने का दबाव बनाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर फिर से कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। हाल ही में विशाल जेल से छूटकर आया था। लगातार मिल रही थी धमकी के कारण युवती और उसकी मां अमखेरा से मकान खाली कर रांझी थाना के रिछाई में रहने लगी थी।

तीन दिन पहले भी युवक ने दी थी धमकी- तीन दिन पहले भी विशाल ने युवती के घर जाकर मां-बेटी को धमकाते हुए केस वापस लेने का दबाव बनाया। विशाल ने धमकी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा। गुरुवार रात करीब 10 बजे विशाल फिर से युवती के घर पहुंचा। युवती के दरवाजा खोलते ही उसने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना में मां-बेटी को पेट और कमर में गंभीर चोट आई। वारदात को अंजाम देने के बाद विशाल बाथरूम के अंदर गया और दरवाजा बंद करने के बाद खुद पर चाकू से हमला कर आत्महत्या कर ली।

मृतक के मामा बोले- भांजे ने युवती से लव मैरिज की थी

मृतक के मामा समर सिंह राजपूत का कहना है कि विशाल उर्फ लोकेश के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे, वह पूरी तरह से निराधार हैं। मृतक ने युवती के साथ लव मैरिज की थी। कुछ दिन साथ में भी रहे। शादी के दो माह के बाद युवती की मां और भाई घर आए और उसे साथ ले गए। इसके बाद गोहलपुर थाने में रेप का केस दर्ज करवाकर लोकेश को जेल भिजवा दिया।

छह माह तक जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिली। पूछताछ में उसने बताया कि मां-बेटी लगातार परेशान कर रहे थे। उसके खिलाफ कभी अधारताल तो कभी गोहलपुर थाने में फर्जी शिकायत कर रहे थे। चार दिन पहले भी युवती और उसकी मां ने अधारताल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

बाथरूम का दरवाजा तोड़कर विशाल को बाहर निकाला गया। अधिक खून बह जाने के कारण विशाल की मौत हो गई। जबकि युवती और उसकी मां की हालत गंभीर बनी हुई है। मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। शव को पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा है। परिजनों के भी बयान लिए जा रहे हैं।

- मानस द्विवेदी,
रांझी थाना प्रभारी